● वर्ष-6
● अंक-88
रायपुर, शनिवार
07 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> साय सरकार की दीपावली...

कांग्रेस देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार: नीतिन नवीन

नई दिल्ली। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेता देश में अस्थिरता और अराजकता की बात कर रहे हैं।

उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या इस कथित योजना की पटकथा उनके इशारे पर लिखी जा रही है और क्या पूरी साजिश का नियंत्रण उनके हाथ में है। नवीन ने कहा कि राहुल गांधी की चुप्पी इन सवालों को और गंभीर बना रही है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के मंत्री खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है।

नवीन ने पूछा कि इस गंभीर बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए। क्या यह उनकी मौन सहमति है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि देश की स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को राहुल गांधी का संरक्षण क्यों मिल रहा है। नवीन ने कहा कि देश उनसे जवाब मांग रहा है।



झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने गुरुवार को बांग्लादेश और नेपाल में सरकारों के गिरने या विरोध का सामना करने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सरकार इसलिए गिर गई, क्योंकि उसने अपने नागरिकों की आवाज नहीं सुनी। नेपाल में भी सरकार ने युवाओं की बात को नजरअंदाज किया और उसे लगा कि उसके पास पूरी ताकत है। अंसारी ने कहा कि भारत में भी छात्र, किसान, मजदूर, कारोबारी और बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। उन्होंने इसे चिंता का संकेत बताया।

राहुल गांधी को लेकर इरफान अंसारी ने क्या दावा किया?

अंसारी ने दावा किया कि दिल्ली में 40 लाख छात्र सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हालात को नियंत्रण में रखा है। अंसारी के मुताबिक, देशभर में लाखों छात्र, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें कानून अपने हाथ में लेने से रोका है। उन्होंने सरकार से इन परिस्थितियों से सबक लेने की अपील की। इसी बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है।

भाजपा ने इरफान अंसारी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?

भाजपा ने इरफान अंसारी के बयान की आलोचना करते हुए इसे अराजकता फैलाने, हिंसा भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश बताया। पार्टी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। नितिन नवीन ने भी अपने पोस्ट के जरिये कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पार्टी के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो राहुल गांधी इस पर अपना रुख साफ क्यों नहीं कर रहे हैं।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

एसआईआर से छूटे मतदाताओं को एक और मौका दें

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों - महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड - तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन मतदाताओं को एक और मौका दें, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के मसौदे से छूट गए थे। 6 नवंबर के एक पत्र में आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) जारी किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) के रूप में चिह्नित करके मतदाता सूची से हटा दिया गया था, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपने फॉर्म फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने कहा है कि ये मतदाता अपने विधिवत भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) को अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं।



इन निर्देशों के तहत, स्पष्ट श्रेणियों के अंतर्गत चिह्नित मतदाताओं की बूथ-वार सूची संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर फिर से लगाई जाएगी। साथ ही, इन सूचियों को संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर पढ़ने योग्य पीडीएफ प्रारूप में भी अपलोड किया जाएगा। इन सूचियों में ड्राफ्ट रोल (प्रारूप मतदाता सूची) में मतदाताओं के नाम शामिल न होने के संभावित कारण दिए गए होंगे। ईसीआई ने जिला चुनाव अधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने ईसीआईएनईटी डैशबोर्ड के जरिए आंशिक रूप से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) नए सिरे से तैयार करें। बूथ लेवल ऑफिसर्स से कहा जाएगा कि वे संबंधित मतदाताओं से संपर्क करें और इन फॉर्म को उन तक पहुँचाना सुनिश्चित करें—चाहे वे फॉर्म सीधे (फिजिकली) दिए जाएँ, या फिर जहाँ भी संपर्क विवरण उपलब्ध हों, वहाँ व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेजे जाएँ। जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, वे उसी ईपीआईसी नंबर का उपयोग करके ईसीआई वेबसाइट या ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से अपने फॉर्म डाउनलोड और भर सकते हैं।

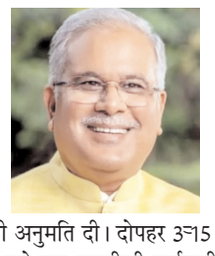
आयोग ने उन मतदाताओं के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं तय की हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उसी राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदल लिया है। जो मतदाता अभी भी उसी पते पर रह रहे हैं, उन्हें अपना भरा हुआ और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही, उन्हें एक लिखित बयान भी देना होगा कि वे पहले यह फॉर्म क्यों जमा नहीं कर पाए। वे ये दस्तावेज खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से जाकर (फिजिकली) जमा कर सकते हैं, या फिर ईसीआईएनईटी पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके ई-साइन के साथ इन्हें जमा कर सकते हैं।

चुनाव याचिका पर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी

हाई कोर्ट में विजय बघेल का बयान दज, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार, 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद और याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने करीब एक घंटे तक उनका प्रतिपरीक्षण किया। हालांकि, सवाल-जवाब की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान अदालत में एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। चुनाव याचिका से जुड़े साक्ष्य के रूप में जमा सीलबंद मोबाइल फोन की बैटरी लंबे समय से बंद रहने के कारण डिस्चार्ज होने की आशंका जताई गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन पेश कर मोबाइल को चार्ज कराने की अनुमति मांगी गई।



अदालत ने सभी पक्षों की मौजूदगी में मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी। दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक तकनीकी कर्मचारी की निगरानी में मोबाइल चार्ज किया गया। करीब 1 घंटे 15 मिनट की चार्जिंग के बाद भी बैटरी महज 13 प्रतिशत तक पहुंच सकी। इसके बाद मोबाइल को बंद कर दोबारा सीलबंद कर दिया गया।

सीलबंद लिफाफे पर विजय बघेल, उनके अधिवक्ता और भूपेश बघेल के अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किए, ताकि साक्ष्य की सुरक्षा और उसकी प्रामाणिकता बनी रहे। 5 नवंबर को जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय बघेल ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और उससे जुड़े तथ्यों पर अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने विजय बघेल से सवाल-जवाब किए।

करीब एक घंटे तक चले प्रतिपरीक्षण के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने इसे अगली सुनवाई में जारी रखने का निर्देश दिया है। अब 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण आगे बढ़ेगा। दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024 में पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले प्रचार बंद होने की निर्धारित अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने समर्थकों के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान चुनावी नारे लगाने और मतदाताओं से वोट मांगने का भी आरोप लगाया गया है।

विजय बघेल ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन बताते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। कथित गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है।

दंतेवाड़ा की माटी से अमेरिका तक बनाई पहचान



रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी से निकलकर सात समंदर पार अमेरिका में अपनी पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले के गणेश कुमार कर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्नेह भरा पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने विदेश में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जुड़े रहने तथा प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को एकजुट करने के उनके प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होने पर गणेश कुमार कर ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पत्र में कहा कि दंतेवाड़ा से अमेरिका तक की श्री गणेश कुमार कर की यात्रा प्रेरणादायक है। विदेश में व्यस्त जीवन के बावजूद अपनी जन्मभूमि, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनका लगाव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे अपनत्व को दर्शाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

विपक्षी नेताओं का लगा जमावड़ा, वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर दिवाली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने शिरकत की। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी को आमंत्रित किया है। दिवाली खुशियां बांटने का त्योहार है और सभी को मिलकर इसे मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी मिलकर मेहनत करेंगे। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी कहा कि दिवाली के मौके पर सभी लोग एक साथ जुट रहे हैं। वहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुलाकात को सुखद और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान नेताओं के बीच बातचीत हुई और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि समारोह का मकसद दिवाली की शुभकामनाएं देना और नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करना है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेताओं के बीच बातचीत होनी चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई रैली बेहद सफल रही। इसकी वजह से लोगों के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि पिछले चुनावों में वोटों की चोरी हुई है।

भारत इलिनॉयस विधानसभा पहुंचने वाली पहली भारतीय

नई दिल्ली। भारत में जन्मी सबा हैदर ने अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार सबा इलिनॉयस राज्य की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई हैं। वह इस राज्य की



जनरल असेंबली में पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। उनकी इस जीत से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि सबा का जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रायन स्कोपा को बड़े अंतर से हराया। परिवार ने इस उपलब्धि को गाजियाबाद, भारतीय समुदाय और पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया है। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में सबा हैदर को कुल 21,996 वोट मिले। उन्हें कुल मतदान का 71.19 प्रतिशत वोट हासिल हुआ। वहीं, उनके प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रायन स्कोपा को 8,902 वोट मिले, जो कुल मतदान का 28.81 प्रतिशत है। इस तरह सबा ने स्पष्ट अंतर से जीत दर्ज की। वह इलिनॉयस की 84वीं डिस्ट्रिक्ट से चुनाव मैदान में थीं। इस जीत के साथ उन्होंने

यूरोप देगा भारत के वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट

ब्रसेल्स/ बेल्जियम। भारत और यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ के 93.5 अरब यूरो (करीब 9,000 करोड़ यूरो से अधिक) के हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। इस समझौते के बाद भारतीय शोधकर्ताओं, कंपनियों और शोध संस्थानों के लिए यूरोप में बड़े स्तर पर शोध करने और उसके लिए सीधे आर्थिक मदद पाने के रास्ते खुलेंगे। यूरोपीय आयोग के मुताबिक, समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों से मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2027 से यह व्यवस्था लागू करने की योजना है। इस समझौते के तहत भारत के वैज्ञानिक और शोध संस्थान हॉराइजन यूरोप के दूसरे स्तंभ यानी पिलर-2 के तहत आने वाली परियोजनाओं में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें यूरोपीय संघ से सीधे अनुदान मिलेगा। खास बात यह है कि भारतीय शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं का नेतृत्व और समन्वय भी कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में शोध को आर्थिक मदद दी जाती है।

अयोध्या में प्रभु के राजतिलक को नतमस्तक होगी सरकार

अयोध्या। अवधपुरी आज फिर त्रेतायुग के उस स्वर्णिम प्रसंग को साकार करने जा रही है, जब वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। रामचरितमानस की चौपाई अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा कै खानी मानो रामनगरी के वर्तमान स्वरूप में जीवंत



हो उठी है। रामकथा पार्क में सजे राम दरबार में राज्य सरकार नतमस्तक होगी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे। इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार देश के उपराष्ट्रपति रामनगरी के इस महापर्व के साक्षी बनेंगे। पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता... रामचरितमानस की इन पंक्तियों का भाव शनिवार दोपहर रामकथा पार्क में साकार होगा। पुष्पक विमान के प्रतीक स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों व संतों के साथ उनका स्वागत करेंगे।

भारत में गुरुद्वारों पर हमलों का दावा, अमेरिका ने उठाए सवाल

वाशिंगटन। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के आयुक्त डेविड एंडरसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि पिछले कुछ सप्ताहों में भारत में सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी शामिल हैं।



एंडरसन ने इन हमलों को लेकर अमेरिकी सरकार से भारत के प्रति अपना रुख सख्त करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को भारत को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को इस बात से जोड़ना चाहिए कि भारत सरकार धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली हिंसा पर क्या कार्रवाई करती है। यानी उनके मुताबिक, भारत की प्रतिक्रिया के आधार पर अमेरिकी सुरक्षा सहायता पर फैसला होना चाहिए। एंडरसन ने कहा कि भारत में पिछले कई सप्ताहों से सिख गुरुद्वारों पर कथित तौर पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये घटनाएं किन राज्यों या शहरों में हुईं, कितने गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया।

इंडिया गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका

एनसीपी गुटों के विलय से एनडीए में आ सकते हैं शरद पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो गुटों के संभावित विलय को लेकर नई बातें सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार, अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट चाहता है कि महाराष्ट्र में दोनों पक्ष फिर से एक हो जाएं। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाला गुट भी एनसीपी के विलय के पक्ष में बताया जा रहा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन जाए। हालांकि, खबरें हैं कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, जिससे एक एकजुट एनसीपी बनने की संभावना को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। ये घटनाक्रम तब सामने आए हैं, जब प्रफुल्ल पटेल ने गुरुवार शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल जाकर वरिष्ठ नेता शरद पवार का हाल-चाल जाना, जो अभी वहां इलाज करा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात के दौरान एनसीपी के गुटों के बीच विलय की संभावना पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शरद पवार को भेजे गए संदेश पर भी बात की। शरद पवार के बार-बार अस्पताल में भर्ती होने के कारण, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार, एक एकजुट एनसीपी की बढ़ती मांग पर सहमत होंगे?

इस विलय से भाजपा को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। पार्टी को एनसीपी खेमे के आठ प्रमुख सांसदों का समर्थन मिल सकता है, जिससे संसद में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, शरद पवार इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं, तो इससे विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ बन रहा राजनीतिक माहौल कमजोर हो सकता है।



इस प्रस्तावित विलय से शरद पवार के गुट को राजनीतिक और मंत्री पद से जुड़े फायदे मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है, और एक एकजुट हृष्टक्क के भीतर उनका राजनीतिक भविष्य भी अधिक सुरक्षित हो सकता है। इसी तरह, हृष्टक्क के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र कैबिनेट में वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है।

खांसी और संक्रमण होने के बाद शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके डॉक्टर के अनुसार, उनमें ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इससे पहले, पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी मिली थी, जहां वे दो दिनों तक भर्ती थे। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाल-चाल जानने के लिए उन्हें फोन किया था। शरद पवार के करीबी दोस्त विट्ठल मनियार ने मीडिया को बताया कि बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता से कहा कि सुप्रिया सुले तैयार हैं और वे देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने पवार से यह भी कहा कि वे देश की चिंता न करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सेहत पर लगाएं।

शरद पवार से मिले एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। पवार (85) का एक निजी अस्पताल में चेस्ट इन्फेक्शन (छाती के संक्रमण) का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें तीन दिन पहले भर्ती कराया गया था। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, उनकी (पवार की) हालत काफी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनकी स्थिति अच्छी है और उनका इच्छाशक्ति भी मजबूत है। शिंदे ने बताया कि अस्पताल में मुलाकात के दौरान, पवार ने राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में पूछा, खासकर सतारा जिले के बारे में।

नक्सलवाद के अंत के बाद बीजापुर में विकास को मिली नई गति

■ तीन वर्षों में 90 से अधिक गांवों तक पहुंची बिजली



बीजापुर। कभी नक्सलवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे रहे बीजापुर के दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में अब बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में जिले के 90 से अधिक ऐसे गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है, जहां पहले विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि 50 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य जारी है। जिले में एक हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

नक्सलवाद के प्रभाव में कमी और बेहतर सुरक्षा वातावरण के कारण अब उन क्षेत्रों तक भी विकास कार्य पहुंच रहे हैं, जहां कभी प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के लिए पहुंचना बेहद कठिन था। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बीजापुर के सहयोग से गर्ल्स पोर्टा केबिन ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजापुर के कलेक्टर श्री विश्वदीप ने जिले में हो रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। शांति से विकास की ओर विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि बीजापुर में विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक तक बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सड़क, बिजली, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रशासन के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। सड़क संपर्क और बिजली की उपलब्धता से जुड़े पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान 90 से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है और 50 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण निर्माण कार्यों के लिए सीमित समय ही उपलब्ध हो पाता था। कई स्थानों पर सुबह शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य दोपहर तक रोकना पड़ता था। उन्होंने दोरनापाल-जगरगुंडा सड़क का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में स्वीकृत यह सड़क वर्ष 2025 के अंत तक पूरी हो सकी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को पहुंचाना कितना कठिन था। अब बदले हुए वातावरण में अंदरूनी क्षेत्रों में भी सड़क और पुल निर्माण के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुंडापुली सहित विभिन्न क्षेत्रों में बरसात के दौरान भी पुलिया निर्माण के प्रयास किए गए हैं। फुंडरी पुल का निर्माण अंतिम चरण में है तथा बेदरे सहित अन्य स्थानों पर भी पुल निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवालों पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू करने और उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

धनतेरस के दिन दुर्ग के फोम फैक्ट्री में भीषण आग

दुर्ग। जामुल थाना क्षेत्र में एक गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है।जामुल थाना क्षेत्र के करुणा अस्पताल के पीछे स्थित जगदंबा गद्दा और फोम से बने फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लगने से



हड़कंप मच गया। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। आग बुझाने के लिए जिला दमकल विभाग, बीएसपी के दमकल और जामुल से दमकल गाड़िया बुलाई गई है। कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए फायर की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के पीछे की दीवार को तोड़कर भी आग पर काबू करने का प्रयाय किया जा रहा है। जगदंबा गद्दा और फोम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है।जल्द ही आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। फोम का गद्दा बनाने का काम किया जा रहा था- प्रशांत पैकरा, सीएसपी, छावनी इस घटना से फैक्ट्री के अंदर रखा माल, 2 से 3 फोर व्हीलर आग की चपेट में आ गई है। आग से फैक्ट्री संचालक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

62 हाथियों की मौज मस्ती ड्रोन कैमरे में कैद, बेफ्रिक घूम रहे हाथी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में इन दिनों 62 हाथियों का दल अलग-अलग समूहों में विचरण कर रहा है। हाथियों की मौजूदगी के बीच अब उनके कई दिलचस्प दृश्य सामने आए हैं। खेतों में धान की फसल खाते, तालाब में नहाते और पानी में अठखेलियां करते हाथियों का ड्रोन से बनाया गया वीडियो सामने आया है। ड्रोन कैमरे से कैद इन दृश्यों में हाथियों का झुंड प्राकृतिक वातावरण में



बेफिक्र होकर विचरण करता नजर आ रहा है। कहीं हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं तालाब में उतरकर नहाते और पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मरवाही वन मंडल के मरवाही परिक्षेत्र में 62 हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है। हाथियों के अलग-अलग समूहों में विचरण करने से उनकी लोकेशन पर विशेष नजर रखी जा रही है। वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल द्वारा हाथियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं, हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी।

पैंगोलिन के शल्क और तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी पकड़े



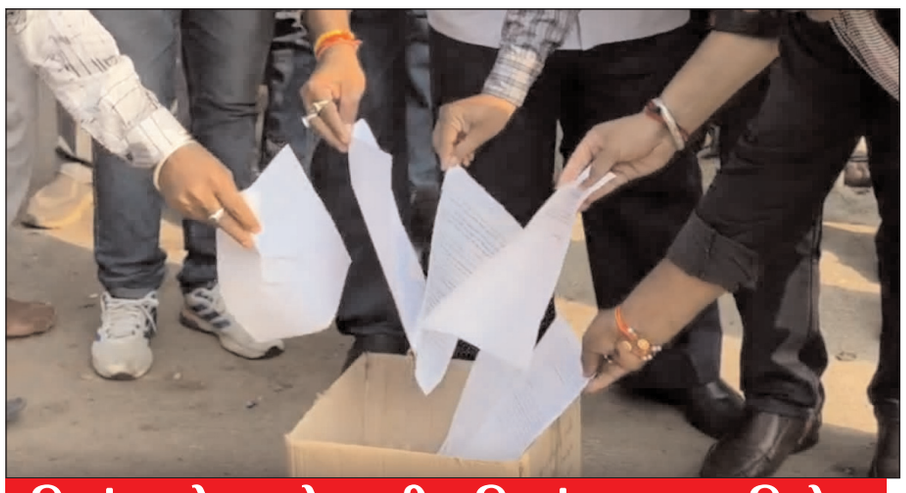
बीजापुर। जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर पैंगोलिन और तेंदुए की एक खाल बरामद की है। दोनों कार्रवाइयों में 6 लोगों को पकड़ा गया है। बरामदगी के बाद विभाग अब वन्यजीवों के शिकार के स्रोत, संभावित खरीदारों और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है। वन विभाग की पहली कार्रवाई तहसील गंगालूर के ग्राम रेड्डी में की गई।

यहां टीम ने दबिश देकर पैंगोलिन के 9।260 किलो शल्क बरामद किए। मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर विभागीय टीम ने दूसरी कार्रवाई भी की। आरोपियों से पूछताछ के बाद तहसील आवापल्ली के ग्राम मल्लेपल्ली, बासागुड़ा में कार्रवाई की गई। यहां से तेंदुए की एक खाल बरामद हुई और दो अन्य लोगों को पकड़ा गया। वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार पैंगोलिन और तेंदुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक में शामिल संरक्षित प्रजातियां हैं। संरक्षित प्रजातियों के जानवरों का शिकार, अंगों के संग्रहण और अवैध कारोबार पर कठोर दंड का प्रावधान है। दोनों मामलों में वन अपराध दर्ज कर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

दो अलग-अलग गांवों से वन्यजीवों के अंगों की बरामदगी के बाद विभाग अब इनके स्रोत का पता लगाने में जुटा है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनका शिकार कहां किया गया और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर संभावित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

खैरागढ़ में पटवारी हड़ताल पर प्रशासनिक कार्रवाई

■ पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध हो रहा है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कार्रवाई की निंदा की है.



निलंबन के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध

खैरागढ़। अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों और शासन-प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है ।प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने धरना स्थल रावण भांठा, इतवारी बाजार में निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। साथ ही अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।

पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने के बाद शासन-प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ निलंबन और कारण बताओ नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की तीन तहसीलों में एक-एक पटवारी को निलंबित किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटवारियों में नाराजगी बढ़ गई है।विरोध स्वरूप उन्होंने धरना स्थल पर निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया।

पटवारियों के आंदोलन को समर्थन देने और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य भी धरना स्थल पहुंचे। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष प्रखर शरण सिंह के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने हड़ताल कर रहे पटवारियों के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर निलंबन और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई करना उचित नहीं है।फेडरेशन ने पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया।

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हमेशा पटवारियों के साथ खड़ा है और उनकी सभी मांगों का समर्थन करता है। सरकार से अपील की कि पटवारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए, ताकि हड़ताल समाप्त हो और प्रभावित राजस्व कार्य दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकें- प्रखर शरण सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर राजस्व पटवारी संघ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में पीवी ऐप को हटाना, वेतन विसंगति दूर करना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना तथा दंडात्मक कार्रवाई और निलंबन वापस लेना शामिल है।

लरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन अलर्ट



बलरामपुर। जिले में दीपावली त्योहार के बीच प्रशासन ने जांच अभियान चलाया है। गुणवत्ताविहीन मिठाई, अमानक खोवा और अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरे जिले में कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दीपावली त्यौहार से पहले वाड्रफनगर राजपुर शंकरगढ़ कुसमी सहित सभी छह विकासखंड में संचालित होटल, ढाबा, मिठाई दुकान तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा निरीक्षण कर मिठाई खोवा मावा पनीर की सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है साथ ही साफ सफाई रखने की हिदायत भी दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले में दीपावली त्यौहार से पहले अब तक 22 प्रतिष्ठानों की औचक जांच कर बालूशाही, रसगुल्ला, मोतीचूर लड्डू, बेसन लड्डू, जलेबी, खोवा, कलाकंद, चमचम और गुलाबजामुन सहित विभिन्न मिठाइयों के 11 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। विजय कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिले के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपयोग करने साथ ही उनका सही रखरखाव साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियो को सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अवैध धान परिवहन और फर्जीवाड़े पर प्रशासन सख्त

कांकेर। राज्य शासन की मंशानुरूप समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर अनिकेत अशोक फड़तरे के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कृषि उपज मंडी समिति बालोद के अंतर्गत आने वाले क्रेता व्यापारी राज हंस राइस इंडस्ट्रीज, संबलपुर के व्यावसायिक परिसर का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम भानुप्रतापपुर ने बताया कि टीम द्वारा फर्म के परिसर में पहुंचकर धान के भौतिक सत्यापन की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर केवल रात्रिकालीन चौकीदार उपस्थित मिला। पूछताछ में चौकीदार ने बताया कि विगत दिवस शाम 7 बजे से लेकर निरीक्षण के समय तक परिसर में धान अनलोड करने के लिए कोई वाहन नहीं पहुंचा है। जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं।

सरगुजा जिले 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले में आगामी 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाली धान खरीदी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में कुल 62 हजार 471 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 67 हजार 929.40 हेक्टेयर है। जिले में पूर्व में संचालित 54 धान उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 नवीन धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन रोशनी व मधु

बीजापुर। जिले की बेटियों रोशनी कुडियम और मधु कुडियम ने अपनी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा के दम पर जिले का नाम रोशन किया है। अंबिकापुर में आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के अंडर-19 बालिका बैडमिंटन वर्ग में दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने रोशनी और मधु को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिले में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि में प्रशिक्षकों के समर्पण और प्रशासन के सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।साधारण परिवारों से आने वाली दोनों खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद नियमित अभ्यास, अनुशासन और कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है।

घरेलू विवाद में महिला हुई घायल, जवानों ने पहुंचाया अस्पताल

सुकमा। जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान पति ने पत्नी के सिर पर वार कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सुकमा रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना नागाराम गांव के पटेलपारा की है। यहां रहने वाली माड़वी सुशीला आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उनका पति माड़वी हिड़मा के साथ विवाद हुआ था। इसी दौरान पति ने पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आने से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल महिला को तत्काल चिंतलनार अस्पताल पहुंचाया।

तीन नवविवाहित जोड़ों को मिले विवाह प्रमाण पत्र

नारायणपुर। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व एवं कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन के मार्गदर्शन में नारायणपुर जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में निवासरत लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत छोटेडोंगर में तीन नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत छोटेडोंगर के उप सरपंच संतोष बैठरू, ग्राम पटेल दीपक बेलसरिया के द्वारा नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इनमें श्रीमती गुलसा मांझी एवं युधिष्ठिर मांझी, श्रीमती जयंती बेलसरिया एवं वासुदेव बेलसरिया तथा श्रीमती यशोधरा मांझी एवं जयसिंह मांझी शामिल हैं। सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके सुखद एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। उल्लेखनीय है कि सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके नजदीकी क्षेत्र में ही विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों एवं शासकीय सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

दीपा सागर की संदिग्ध मौत पर उठे गंभीर सवाल, पूर्व विधायक संतोष से जुड़े बाफना लाइफस्टाइल स्टोर की भूमिका की भी हो निष्पक्ष जांच: समीर खान

जगदलपुर। जगदलपुर में दीपा सागर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कार्यस्थलों पर नाबालिग बच्चियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपा सागर काम करने के उद्देश्य से जगदलपुर स्थित बाफना लाइफस्टाइल स्टोर, जो पूर्व विधायक जगदलपुर विधानसभा संतोष बाफना जी से जुड़ा हुआ है, वहां गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। पुलिस द्वारा प्रारंभिक तौर पर इसे हैंगिंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार को इस घटना की पूरी सच्चाई जानने और न्याय पाने का अधिकार है।



आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता एवं प्रदेश संगठन मंत्री, बस्तर जॉन प्रभारी समीर खान ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक बच्ची काम करने के उद्देश्य से किसी प्रतिष्ठान में जाती है और फिर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, जिस पर केवल प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पर्दा डाल दिया जाए। आखिर उस दिन स्टोर में क्या हुआ था? बच्ची किन परिस्थितियों में थी? उसके साथ काम करने वाले लोगों को घटना के संबंध में क्या जानकारी है? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आना चाहिए।

समीर खान ने कहा कि पूर्व विधायक संतोष बाफना जी से जुड़े प्रतिष्ठान का नाम इस मामले में सामने आने के कारण पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जांच में किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक रसूख, पद, प्रतिष्ठा या प्रभाव आड़े नहीं आना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है और जांच भी बिना किसी दबाव के होनी चाहिए।

आम आदमी पार्टी की पुलिस प्रशासन से प्रमुख मांगें

उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच: दीपा सागर की मौत के मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

सीसीटीवी फुटेज की जांच: बाफना लाइफस्टाइल स्टोर एवं आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग तत्काल सुरक्षित कराई जाए। घटना से पहले और बाद के फुटेज की बारीकी से जांच की जाए।

संबंधित लोगों से पूछताछ : स्टोर में मौजूद कर्मचारियों, प्रबंधन और घटना से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों से निष्पक्ष पूछताछ की जाए।

भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

सुकमा। अवैध शराब के कारोबार और तस्करी के खिलाफ सुकमा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। %ऑपरेशन आगाज% अभियान के तहत छिंदगढ़ पुलिस ने एनएच-30 पर घेराबंदी कर एक वाहन से बल्क लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई में शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन सहित कुल 5 लाख 26 हजार 80 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक, 6 नवंबर की रात गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि सुकमा की ओर से एक वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप लाई जा रही है।सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी छिंदगढ़ आशीष वासनिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनएच-30 स्थित छिंदगढ़ बस स्टैंड चौक पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।इस दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया। पुलिस ने वाहन से बीयर की 52 बोतलें, अंग्रेजी शराब 95 पौवा बरामद किए। जब्त



शराब की कुल मात्रा 50।900 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 26 हजार 80 रुपए है। मामले में छिंदगढ़ के गांधी चौक निवासी 35 वर्षीय लच्छू राम बातिंग को गिरफ्तार किया गया। शराब परिवहन में इस्तेमाल वाहन की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना छिंदगढ़ में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।अब पुलिस शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाने में लगी है।पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देशन, एएसपी मनोज तिर्की के मार्गदर्शन और एसडीओपी मनीष कुंवर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।

संक्षिप्त समाचार

मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य विभाग ने किया निरीक्षण



रायपुर। त्योहारी सीजन में आम नागरिकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से रायपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के तीन प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विभिन्न मिठाइयों के कुल पांच विधिक नमूने संग्रहित किए। निरीक्षण के दौरान दो प्रतिष्ठानों में कमियां पाए जाने पर उन्हें इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक श्री दीपक कुमार अग्रवाल (आईएएस) ने त्योहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया जा रहा है।

एक सप्ताह में 3 आरोपियों से देसी कट्टा समेत हथियार जब्त



रायपुर। नॉर्थ जोन पुलिस ने एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अ ल ग - अ ल ग मामलों में कुल 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुढियारी में एक आरोपी के पास से देशी कट्टा बरामद किया गया। वहीं, जुआ खेलते पकड़े गए 36 लोगों से 1 लाख 26 हजार 100 रुपए और ताश की 52 पत्तियां जब्त की गईं। पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) दीपमाला कश्यप के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज कर 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आबकारी एक्ट के 8 मामलों में 8 और धारा 36(सी) के तहत 4 मामलों में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं बीएनएसएस की धारा 170 के तहत 70 मामलों में 71 लोगों और धारा 126/135(3) के तहत 78 मामलों में 85 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा अलग-अलग थानों में 35 वारंट तामील कराए गए।

रविवार को महावीर निर्वाण दिवस पर मांस - मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जारी आदेश पर महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम के परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश रायपुर नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। महावीर निर्वाण दिवस पर रविवार 8 नवंबर को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन विक्रय की दुकानों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवस महावीर निर्वाण दिवस पर मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित स्थल पर तत्काल उसकी जप्ती करते हुए संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री की पाती में ग्राम लिम्हा की सुनीता के प्रयासों की सराहना



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले के ग्राम लिम्हा की सुनीता बहन को आत्मीय पाती लिखकर उन्हें और उनके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने पत्र में बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि घर की जरूरतों के बीच बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना प्रशंसनीय है। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि महतारी वंदन योजना की राशि से सुनीता बहन को स्कूल वैन का किराया और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना संचालित की जा रही है, ताकि महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने सुनीता बहन के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खूब पढ़ने, अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर मिलने की शुभकामनाएं दीं। साथ ही विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प में बच्चों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अनुदान वितरण प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी और सरल : मुख्य सचिव



रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को कृषि के क्षेत्र में और अधिक संबल प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत किसानों को आदान सहायता (अनुदान) राशि प्रदान करने की प्रक्रिया, पात्रता के दिशा-निर्देशों और डेटाबेस एकीकरण पर विस्तार से मंथन किया गया।

बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित होना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग के विभिन्न पोर्टलों और धान खरीदी डेटाबेस को आपस में एकीकृत करने पर जोर दिया, जिससे किसानों से बार-बार दस्तावेज या जानकारी मांगने की आवश्यकता न पड़े। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान आईडी, फार्म आईडी और गिरदावरी के आंकड़ों को आपस में जोड़कर किसानों की कुल भूमि और फसल के रकबे की जानकारी का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसानों को अपनी विशिष्ट फार्म आईडी की पुष्टि करने तथा योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने की सहज सुविधा दी जाए। योजना के सुचारू संचालन हेतु योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित भूमि पर धान की फसल दर्ज होना आवश्यक है। धान खरीदी प्रक्रिया के अंतर्गत कम से कम एक सफल खरीदी का लेन-देन होना जरूरी है, जिसके लिए खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल की जानकारी का उपयोग किया जाएगा।

किसानों के हितों की रक्षा और वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए धान खरीदी के दौरान टोकन जारी करते समय अनुदानित रकबे का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर पर, पिछले वर्ष धान न बेचने वाले किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, बैठक में दलहन, तिलहन और मिलेट्स (कोदो-कुटकी-रागी) की खरीदी व्यवस्था तथा इन फसलों के उत्पादक किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी प्रसारित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने ग्रामीण अंचलों में योजना की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया, ताकि किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदवार और प्रबंध संचालक मार्कफेड जितेन्द्र शुक्ला सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन 15 को छत्तीसगढ़ आएंगे

तैयारियों के लिए 11 को आएंगी स्मृति



रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस दौरान वे रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर नितिन नबीन छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन में तैयारियां शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को राजनीतिक और संगठनात्मक लिहाज से अहम माना जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि वे सीधे धरमजयगढ़ जाएंगी और कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करेंगी।

धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में नितिन नबीन की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके दौरे से पहले प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी का पहुंचना संगठन की तैयारियों को लेकर भाजपा की गंभीरता को दर्शाता है। अब प्रदेश की सियासत में 15 नवंबर के इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पीएम आवास शहरी 2.0 को स्वीकृति मिलने पर सांसद संतोष पांडेय ने जताई खुशी

कहा- जिन आवासों को भूपेश बघेल ने रोका था, साय सरकार ने सबसे पहले किया



रायपुर। पीएम आवास शहरी 2.0 को स्वीकृति मिलने पर सांसद संतोष पाण्डेय खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पहला काम सरकार ने आवास का किया। जिन आवासों को भूपेश बघेल ने रोका था, साय सरकार ने पहले हस्ताक्षर किया। 84 नगरीय निकायों के लिए नए आवास स्वीकृत हुए हैं। हर व्यक्ति के सिर पर छत होना चाहिए, सरकार चिंता करती है।

सांसद संतोष पांडेय धनतेरस के अवसर पर मीडिया से रू-ब-रू हुए। इस दौरान उन्होंने एक हजार से अधिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं को तोहफा दिया है। अग्निवीर की सौगात के बाद यह बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है।

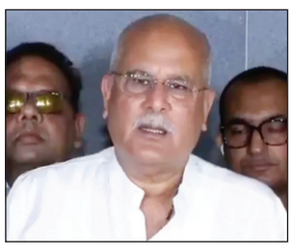
वहीं कांग्रेस रैली में शामिल नहीं होने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई पर सांसद ने कहा कि अपने-अपने विरोधियों की सूची बनाकर भेज रहे हैं। कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो कुछ लोग करवाने के लिए भी है। कांग्रेस में सिर फुटव्वल देखने मिल रहा है।

दीपक बैज के बयान कि कांग्रेस अर्जुन है, हर चक्रव्यूह को तोड़ेगी, पर सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि यह अर्जुन नहीं, दुर्योधन है, और 10 जनपद में गांधारी पट्टी बांधकर बैठी है। उनको अपने पुत्र दुर्योधन के सिवाय कोई नहीं दिखता। महाभारत में उनका सत्यानाश होता है। कांग्रेस का पतन होने वाला है।

वहीं रामलीला मैदान में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि सभा में मंच और कुर्सियां, दोनों ही खाली थी। कांग्रेस की औकात आप देख सकते हैं। इसके साथ बस्तर में कई गांवों में जलेंगे दीप पर सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि कोंटा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर में खुशी का माहौल है। अमन और चैन की बयार आज बह रही है। दीपों की रौशनी से बस्तर जगमगाएगा।

सोनिया को 'गांधारी' बताए जाने पर बिफरे भूपेश

कहा- भाजपा नेताओं का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन



रायपुर। सांसद संतोष पाण्डेय के सोनिया गांधी को 'गांधारी' और कांग्रेस को 'दुर्योधन-दुशासन' कहे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि हम उनको पागल कर देंगे।

राहुल गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। भाजपा मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे की बातें कह रही। अमित शाह कहते थे कि संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन रायपुर में आकर कहते हैं कि राहुल गांधी सड़क पर नहीं, संसद में बात करें। राहुल गांधी संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं।

वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के नेहरू को लेकर दिए बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा पागल आदमी है। नेहरू जी के समय बांग्लादेश बना ही नहीं था, बांग्लादेश तो इंदिरा गांधी के समय बना था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रंप का फोन आया, सीजफायर हो गया। हमारे जवान आगे बढ़ चुके थे, फिर उन्हें रोका क्यों गया? क्या फादरलैंड से फोन आ गया था, इसलिए ऑपरेशन रोक दिया गया? धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए थी। सरकार ने धान खरीदी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रदेश में पटवारी हड़ताल पर हैं। सरकार की धान खरीदी करने की नीयत नहीं है। सरकार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग बातें कर रही है। इस सरकार में किसान परेशान हैं। सरकार को धान खरीदी के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

पार्षदों ने ही जोन कार्यालय में लगाया ताला



रायपुर। जब नगर निगम के पार्षद अपने ही कार्यालय में तालाबंदी कर दें तब कामकाज का हाल क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी की मुसीबत व परेशानी भी समझ सकते हैं। सफाई,बिजली व पानी की समस्या ही मुख्य कारण हैं और पार्षदों को अब समझ आ गया कि उनके वार्ड में काम हो नहीं रहा। रायपुर नगर निगम के जोन-8 कार्यालय महोबाबाजार में शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। जनता के मूलभूत काम नहीं होने और लगातार अनदेखी से नाराज पार्षद नारेबाजी करते हुए जोन कार्यालय में ताला बंद कर बैठ गए है। मामले पर महापौर,आयुक्त व जोन आयुक्त का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। बता दें दीपावली से पहले सफाई व रोड लाइट को प्राथमिकता से पूरा करने का आदेश निगम मुख्यालय से जारी हुआ था। आज सड़कों पर कचरों का अंबार हैं और हर वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों का सवाल जब टैक्स लेने के लिए घर दुकान की सीलबंदी तक कर देते हैं फिर सुविधा देने में कोताही क्यों बरतते हैं? जोन कार्यालय में पार्षदों ने कर्मचारियों को फटकार लगाई और कार्यालय से बाहर जाने को कहा। इसके बाद सभी कर्मचारियों को बाहर निकलवाकर कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद एक साथ नजर आए। जोन अध्यक्ष भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि निगम प्रशासन जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है।क्षेत्र में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से जुड़े काम अटके हुए हैं। शिकायतों के बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।

डिजिटल और पेपरलेस विधानसभा की ओर छत्तीसगढ़ का बड़ा कदम

■ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न



रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा को आधुनिक तकनीक से लैस करने तथा इसकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम, सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसी उद्देश्य के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA – National e-Vidhan Application) के प्रभावी क्रियान्वयन और सुचारू उपयोग को लेकर आयोजित दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को NeVA'k एप्लीकेशन की तकनीकी एवं व्यावहारिक बारीकियों से अवगत कराना था, ताकि विधायी कार्यों में डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल से विधानसभा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) के NeVA समन्वयक श्री अमन गौतम और श्री श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के उपयोग एवं संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण उपस्थित प्रतिभागियों को प्रदान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को निम्नडिजिटल कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण दिया गया। डिजिटल माध्यम से विधानसभा के प्रश्न और सूचनाएं प्रस्तुत करना, विधायी दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रबंधन एवं सुरक्षित रख-रखाव, सदन की कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, विभिन्न संसदीय और विधायी प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित करना शामिल है। विशेषज्ञों ने बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कामकाज न केवल बेहद सरल और त्वरित होगा, बल्कि इससे कार्य निष्पादन में भी उच्च स्तर की प्रभावशीलता आएगी।

इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जोड़कर उन्हें पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और कागज रहित (पेपरलेस) स्वरूप देना है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में (NeVA) के इस प्रभावी क्रियान्वयन से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन और सूचनाओं के आदान-प्रदान में क्रांति आएगी।

सेंट्रल जेल पहुंचे भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल से की मुलाकात

■ कहा- कांग्रेस कोषाध्यक्ष को सरकार ने गलत तरीके से जेल में रखा



रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। जेल के भीतर दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी और जेल में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामगोपाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। सरकार ने उन्हें गलत तरीके से जेल में बंद कर रखा है।

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 5 नवंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से रामगोपाल अग्रवाल को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, कोल घोटाले समेत अन्य मामलों में आरोपी होने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। शराब घोटाले में जमानत मिलने के बावजूद अन्य मामलों में राहत नहीं मिलने से उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी है। सेंट्रल जेल में मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि 4 मामले अभी लंबित हैं। इन चारों में जमानत मिलने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। रिजवी का दावा है कि किसी भी एफआईआर में रामगोपाल का नाम नहीं है। उन्हें पहले से अपराधी एक आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए कहा, कांग्रेस कोषाध्यक्ष होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग, (छ. ग.)

ईश्तहार सूचना प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग एवं सहायक आयुक्त आबकारी जिला-दुर्ग (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा, 34 (2) के अंतर्गत अवैध मदिरा परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर नीचे वर्णित जप्तशुदा वाहन को अधिनियम की धारा 47 (क) (2) के अंतर्गत अधिहरण, राजसात करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। जिसपर इस न्यायालय में प्रकरण संस्थित कर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला-दुर्ग से वाहनस्वामी की जानकारी लिया जाकर तद्नुसार वाहनस्वामी को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया किन्तु पता अपूर्ण होने पर नोटिस अदम तामिल वापस प्राप्त हुआ है :-

स0 क्र0	प्रकरण क्रमांक	अनावेदक का नाम/पता	जप्त वाहन का प्रकार	वाहन नबर	वाहनस्वामी का नाम / स्थाई पता
1	202608100100034	युगल शर्मा आ0 लल्ला प्रसाद शर्मा एवं अन्य 01	मोटर सायकल बुलेट	सी.जी.-04-एल. डी.-5644	हेमलता गुप्ता पति अरूण गुप्ता पता-मकान नं. 587 जनता कालोनी एकता नगर रायपुर तह0 व जिला रायपुर (छ0ग0)
2	202607100100003	संतोष जागड़े आ0 बिसहत जांगड़े	मोटर सायकल होण्डा साईन	सी.जी.-07-ए. क्यू-3475	लुकेश्वर साहू पिता सीताराम साहू पता-झलमला तह0 व थाना बालोद जिला-बालोद
3	202607100100005	मुकेश नवरंगे उर्फ नजरू आ0 हरियर नवरंगे	वाहन मोटर सायकल	सी.जी.-07-सी. डी.-7220	मुकेश कुमार पिता-हरियन, पता-गाड़ाडीह पो0 कानाकोट तह0 पाटन थाना उतई जिला दुर्ग (छ0ग0)
4	202511100100053	बृज मोहन माल्या आ0 नरेश माल्या	मोटर सायकल टी.वी.एस.रेडॉ	चेचिस नंबर MP625BK27M3M03336 इंजन नंबर BL2AM3103298	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के ऑनलाईन रिकार्ड में वाहनस्वामी का नाम पता पंजीकृत नहीं है।
5	202412100100016	मुरली साहनी आ0 शिवनाथ	मोटर सायकल हीरो होण्डा	सी.जी.-07-एल. वाय.-4276	एमडी इरशाद आ0 एमडी ईश्शा पता-फरीद नगर सुपेला भिलाई जिला-दुर्ग (छ0ग0)
6	100/2026	हेमंत निर्मलकर आ0 संतराम निर्मलकर एवं अन्य 01	मोटर सायकल होण्डा टिवस्टर	सी.जी.-07-एल. के.-5511	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के ऑनलाईन रिकार्ड में वाहनस्वामी का नाम पता पंजीकृत नहीं है।

उक्त् जप्तशुदा वाहन के वाहनस्वामियों को अंतिम बार सूचित किया जाता है, कि जप्तशुदा अपने वाहन के संबंध में अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 19/11/2026 समय - 03.00 बजे। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग के समक्ष उपस्थित होवे। अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

जी-262704451/3

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दुर्ग (छ.ग.)

चुनाव आयोग में विवाद पर विराम

प्रशांत तिवारी

चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपने भीतर किसी तरह के मतभेद या विवाद होने की खबरों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि उसके सभी फैसले आपसी सहमति से लिए गए हैं और कामकाज में किसी तरह की असहमति नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को दो चुनाव आयुक्तों की ओर से जुलाई में लिखे गए पत्र किसी नीतिगत मुद्दे या आईटी विभाग से जुड़े अधिकारों को लेकर नहीं थे, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज और उनके जारी किए गए आदेश से संबंधित थे। दरअसल, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने जुलाई 2026 में आयोग में कार्य आवंटन को लेकर आपत्ति जताई थी। दोनों ने कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर बिना चुनाव आयुक्तों की सहमति के विभागों के कामकाज में बदलाव किए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आयोग में कार्य आवंटन के रोस्टर और आदेश जारी करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि निर्धारित नियमों और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। आयोग के मुताबिक, 28 जुलाई 2026 को प्रतिनियुक्ति पर आए अतिरिक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग ने काम के बंटवारे को लेकर एक कार्यालय आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत आईटी और जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) का प्रभार उप चुनाव आयुक्त संजय कुमार से लेकर आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को सौंप दिया गया था। इसके बाद सीमा खन्ना सीधे आयोग के प्रति जवाबदेह हो गई थीं। इस आदेश पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई। दोनों ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर अधिकारी के आदेश और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। हालांकि, आयोग ने साफ किया कि इन पत्रों में किसी नीतिगत विषय या आईटी विभाग की निगरानी के अधिकार को लेकर शिकायत नहीं की गई थी। मामले में 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर निर्देश जारी किया। इसके बाद 28 जुलाई को जारी कार्य आवंटन का आदेश लागू नहीं हुआ। आयोग ने स्पष्ट किया कि आईटी विभाग की निगरानी का अधिकार कभी किसी से वापस नहीं लिया गया था। साथ ही, दोनों आयुक्तों की ओर से उठाए गए मुद्दों का समाधान हो चुका है और अब इस मामले में किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद संजय कुमार को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। वहीं, आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को पहले की तरह फाइलें भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन उस समय इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ था। करीब एक महीने बाद आयोग में नए उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा की नियुक्ति हुई। उनके आने के बाद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का नए सिरे से आवंटन किया गया और इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए। नई व्यवस्था के तहत अब सीमा खन्ना अपनी फाइलें उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग को भेजेंगी। हालांकि, उनकी रिपोर्टिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पहले की तरह उप चुनाव आयुक्त (डीईसी) स्तर के अधिकारी को ही रिपोर्ट करती रहेंगी। इस तरह आयोग में फाइलों के आवागमन और कार्य आवंटन की पुरानी व्यवस्था फिर बहाल हो गई है। गौरतलब है कि 23 सितंबर 2025 को जारी कार्यालय आदेश के तहत आयोग में आईटी, जन शिकायत और मतदाता सूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उप चुनाव आयुक्त संजय कुमार को सौंपी गई थीं।

पंजाब की सियासत में कमल की दस्तक और 'आप' का अंतर्विरोध

अशोक भाटिया

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखें अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को अपने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के ठीक बाद, पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी एक बड़े विस्फोट में बदल गई है। अमृतसर नॉर्थ से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा, और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा का एक साथ पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना केवल तीन विधायकों का इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक गहरा राजनीतिक और नैतिक झटका है। नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 2 नवंबर 2026 को जिस तरह इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, उसने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है कि क्या पंजाब में भी भाजपा का बहुचर्चित %ऑपरेशन लोटस% पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका है।

इस राजनीतिक उठापटक को समझने के लिए इसके कालक्रम और पृष्ठभूमि को देखना अनिवार्य है। विपक्षी खेमे और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पंजाब में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने या सत्ता परिवर्तन की इस पटकथा की शुरुआत हाल-फिलहाल में नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। मार्च 2024 और उसके बाद के महीनों में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का एक बड़ा धड़ा, जिसमें राघव चड्ढा और डॉ. संदीप पाठक जैसे प्रमुख चेहरे शामिल थे, धीरे-धीरे पार्टी लाइनों से दूर हुआ और बाद में 7 राज्यसभा सांसदों के एक गुट ने तकनीकी रूप से भाजपा के साथ विलय का रास्ता चुना, तभी से पंजाब की सत्ताधारी पार्टी के भीतर दरारें साफ दिखाई देने लगी थीं। उस समय भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे गद्दारी करार दिया था और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में किया गया दलबदल बताया था। इसके बाद जब भगवंत मान सरकार ने जालंधर में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई, तो 94 विधायकों में से केवल 65 विधायक ही वहां पहुंचे। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि पार्टी के लगभग 29 विधायक या तो नेतृत्व से नाराज थे या किसी अन्य



राजनीतिक विकल्प की तलाश में थे। अब, नवंबर 2026 की शुरुआत में तीन सिटिंग विधायकों का इस्तीफा देना इसी सिलसिले की अगली और अधिक आक्रामक कड़ी है।

संसदीय लोकतंत्र में जब भी किसी राज्य में सत्ताधारी दल के विधायक विपक्षी दल में शामिल होते हैं, तो सत्ता पक्ष द्वारा इसे ऑपरेशन लोटस की संज्ञा दी जाती है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा धनबल, बाहुबल और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के डर का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। देश के राजनीतिक इतिहास में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में सरकारों का गिरना या विधायकों का बड़े पैमाने पर दलबदल करना इस रणनीति का हिस्सा माना जाता रहा है। पंजाब के संदर्भ में भी, तीन विधायकों के भाजपा में जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका तर्क है कि पंजाब की जनता ने 2022 में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों का प्रचंड बहुमत देकर बदलाव की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, भाजपा उसे चोर दरवाजे से हथियाना चाहती है। हालांकि, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं, वे केवल राजनीतिक अवसरवाद की कहानी नहीं कहते, बल्कि वे शासन और प्रशासन की गंभीर विफलताओं की ओर इशारा करते हैं।

इस्तीफा देने वाले तीनों नेताओं—कुंवर विजय प्रताप, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा—ने मीडिया के सामने आकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने 2015 के कोटकपूरा और बहबल कलां गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले की जांच करने वाली एसआईटी का नेतृत्व किया था, लंबे समय से आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट चल रहे थे। उनका आरोप है कि जिस बेअदबी मामले को सुलझाने और दोषियों को सजा दिलाने के वादे पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस पर मान सरकार ने जानबूझकर ढीली पैरवी की और राजनीति की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पंजाब के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस के दावों पर सवाल उठाए और राज्य में फैले माफिया राज की निंदा की। वहीं, पूर्व मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सीधे तौर पर पंजाब में बढ़ते नशे (चिट्टा) के कारोबार, कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने, बेलगाम गैंगस्टर संस्कृति और राज्य पर बढ़ते ढाई लाख करोड़ रुपये के कर्ज को अपनी नाराजगी का कारण बताया। इन नेताओं का सबसे गंभीर आरोप यह है कि पंजाब की चुनी हुई सरकार को चंडीगढ़ से नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे कुछ खास लोगों और उनके सलाहकारों (जैसे विभव कुमार) द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की गरिमा को ठेस पहुंची है।

इस मोड़ पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कितने और विधायक या नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं? राजनीतिक गलियारों और खुफिया रिपोर्टों में यह चर्चा आम है कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 20 से 30 विधायक भाजपा और कांग्रेस के संपर्क में हैं। विशेष रूप से वे विधायक, जिन्हें डर है कि 2027 के चुनावों में उनका टिकट काटा जा सकता है, या जो भगवंत मान की कार्यशैली से लंबे समय से असंतुष्ट हैं, वे बहुत जल्द बड़ा कदम उठा सकते हैं। भाजपा के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया और राज्य इकाई के अध्यक्ष के अनुसार, यह केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कई और बड़े चेहरे भाजपा में शामिल होंगे क्योंकि झाड़ू का कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है। पार्टी के भीतर असंतोष का मुख्य कारण टिकट वितरण की नीति और हाल ही में किए गए संगठनात्मक बदलाव हैं। उदाहरण के लिए, समाना निर्वाचन क्षेत्र में चेतन सिंह जौड़ामाजरा की अनदेखी कर शिरोमणि अकाली दल के पूर्व वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह रखड़ा को हलका इंचार्ज बना दिया गया, जिससे जौड़ामाजरा का टिकट कटना तय माना जा रहा था। इसी प्रकार, कई अन्य क्षेत्रों में भी पुराने वफादारों को दरकिनार कर पैराशूट नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जो आने वाले समय में एक बड़ी भगदड़ का कारण बन सकता है।

भाजपा के लिए पंजाब हमेशा से एक कठिन राजनीतिक मैदान रहा है, विशेष रूप से तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलनों के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब, शिरोमणि अकाली दल के कमजोर होने और आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस घमासान के बीच, भाजपा पंजाब में अपने दम पर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर हिंदू और सिख चेहरों को अपने पाले में लाकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सिख चेहरे के रूप में कुंवर विजय प्रताप की साफ-सुथरी छवि का उपयोग भाजपा माझा और मालवा क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए करेगी। वहीं जौड़ामाजरा और पठानमाजरा जैसे जमीनी नेताओं के आने से पटियाला और उसके आसपास के जिलों में भाजपा का सांगठनिक ढांचा मजबूत होगा। भाजपा का यह रणनीतिक कदम स्पष्ट करता है कि वह पंजाब में केवल एक छोटी हिस्सेदार बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि 2027 में डबल इंजन की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

दरअसल पंजाब की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील और अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। आम आदमी पार्टी जिसे अपनी सबसे सुरक्षित राजनीतिक जागीर समझ रही थी, वहां आंतरिक कलह और अंतर्विरोधों के कारण दरारें साफ दिखने लगी हैं। पहली लिस्ट आते ही जो बगावत शुरू हुई है, उसने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का अति-केंद्रीकरण और विधायकों की आवाज को दबाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती हो सकता है। यह घटनाक्रम केवल विधायकों के दलबदल का मामला नहीं है, बल्कि यह पंजाब की जनता के उस जनादेश की परीक्षा है जो उसने पारंपरिक पार्टियों को नकार कर एक इंकलाब के नाम पर दिया था। यदि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल समय रहते अपने विधायकों के असंतोष को दूर करने और शासन व्यवस्था में सुधार करने में विफल रहते हैं, तो पंजाब में कमल का खिलना केवल समय की बात रह जाएगी। आगामी महीनों में होने वाले दलबदल और गठबंधन के नए समीकरण ही यह तय करेंगे कि पंजाब की कमान किसके हाथ में होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का किला भीतर से दरक रहा है और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक साफ सुनी जा सकती है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

23-योगाचार का विज्ञानवाद



गतांक से आगे...

वसुबन्धु पहिले सर्वास्तिवादी था परन्तु असङ्ग के प्रभाव से वह विज्ञानवादी योगाचार हो गया था। यह किम्वदन्ती चली आती है कि मैत्रेय ने जो कि भविष्य में होने वाले बुद्ध का नाम है तुषित नामक स्वर्ग में असङ्ग पर कई ग्रन्थ प्रकट किये, जिनका रचयिता असङ्ग समझा जाता है। परन्तु वास्तविक तथ्य यह प्रतीत होता है कि मैत्रेयनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जो कि असङ्ग का गुरु था और मैत्रेयनाथ ही वस्तुत: विज्ञानवाद का प्रवर्त्तक था। अभिसमयालङ्कार कारिका जिसका दूसरा नाम प्रज्ञापारमितोपदेश भी है, मैत्रेयनाथ का बनाया हुआ ही ग्रन्थ है। इसी प्रकार महायान सूत्रालङ्कार जिसे सिल्वेन लेवी ने ढूँढा था और असङ्ग की रचना बताया, वह भी मैत्रेयनाथ का ही ग्रन्थ है। उपयुक्त मैत्रेयनाथ के ग्रन्थों के सिवाय

जो भूल से असङ्ग के ग्रन्थ समझे जाते हैं, महायान-संपरिग्रह आदि असङ्ग के ग्रन्थ हैं जो कि मूल संस्कृत में नष्ट हो चुके और केवल चीनी अनुवाद में विद्यमान हैं।

परन्तु जहाँ तक दार्शनिक विज्ञानवाद है, उसके विषय में प्रकाश डालने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक वसुवन्धु की विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि है। विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में दो ग्रन्थ सम्मिलित हैं, एक तो विंशतिका जिस पर स्वयं बसुबन्धु की टीका है और दूसरी त्रिंशिका जिस पर स्थिरमति की टीका है। इन दोनों का सिल्वेन लेबी ने पता लगाया। पेरिस से यह दोनों ग्रन्थ विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि के नाम से संस्कृत रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। विज्ञानवाद के और भी अनेक ग्रन्थों का पता चल चुका है, परन्तु फिर भी आधुनिक समय में विज्ञानवाद के सिद्धान्तों के समझने का हमारा मुख्य स्रोत वैदिक दार्शनिक लेखक ही हैं।

क्रमश: ...

नरक चतुर्दशी

शिवानी अवस्थी

दिवाली का त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि पांच दिनों तक चलने वाला खुशियों और उत्साह का पर्व है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अपना अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसी दौरान नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का नाम भी खूब सुनने को मिलता है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली दो अलग-अलग त्योहार हैं या फिर दोनों एक ही पर्व के नाम हैं?

साल 2026 में नरक चतुर्दशी की तिथि को लेकर पंचांगों में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। कुछ कैलेंडर छोटी दिवाली 7 नवंबर को बता रहे हैं, जबकि उदयातिथि और अभ्यंग स्नान की गणना के अनुसार नरक चतुर्दशी 8 नवंबर को भी बताई गई है।



दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे शुरू होकर 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे तक रहेगी। इसलिए स्थानीय पंचांग और पूजा की परंपरा के अनुसार तिथि का निर्धारण करना उचित होगा।

दरअसल, नरक चतुर्दशी को ही आमतौर पर छोटी दिवाली कहा जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का वध करने की कथा याद की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है।

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, घर की साफ-सफाई करने और दीपक जलाने की परंपरा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का क्या संबंध है, इस दिन क्या किया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। जी हां, सामान्य तौर पर नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली एक ही पर्व के दो नाम हैं। नरक चतुर्दशी इसका धार्मिक नाम है, जबकि छोटी दिवाली इसे मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने के कारण कहा जाता है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसे नरक चौदस, रूप चौदस और कुछ स्थानों पर काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों के साथ जुड़ी परंपराओं में क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नाम के राक्षस ने लोगों को परेशान कर रखा था और कई लोगों को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उसका वध किया और बंदियों को मुक्त कराया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की इस विजय की खुशी में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

छोटी दिवाली के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। कई परिवारों में तिल के तेल से अभ्यंग स्नान यानी तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। इसे शरीर और मन की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा घर की साफ-सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है और शाम के समय घर के बाहर तथा पूजा स्थल पर दीपक जलाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यम दीपदान की भी परंपरा है।

मिड टर्म चुनाव में हारते ही महाभियोग में फंसे ट्रंप!

अभिनय आकाश

अमेरिका में ट्रंप की सबसे बड़ी हार। वो ट्रंप जो कि मोदी को हराने की उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की बात करते थे। कमला हैरिस ने तंज कसा। भारतीय मूल के नेताओं ने जमकर अमेरिकी चुनाव में धमाल मचाया है। सोचिए जिस नेता ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की बार-बार कोशिश की हो या धमकाया हो। जिस नेता ने चुनावी रैलियों में दावा किया कि अमेरिका की जनता उसके साथ खड़ी है। आज उसी नेता को अपनी ही पार्टी की चुनावी हार पर सफाई देनी पड़ रही है। अमेरिका से मिड टर्म चुनाव के जो शुरुआती नतीजे सामने आने लगे उन्होंने वाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद तक हलचल मचा दी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों सदनों में बढ़त बनाती नजर आ रही या यह कह सकते हैं कि ट्रंप की हार हो चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ रहा होता तो हम भारी बहुमत से जीतते। यानी वह कह रहे हैं कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा था। अब सवाल है कि अगर ट्रंप इतने ही लोकप्रिय हैं तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार पीछे क्यों रह गए? क्या अमेरिकी जनता ने ट्रंप की नीतियों को नकारना शुरू कर दिया है? क्या महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे ने राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर महाभियोग का खतरा मडराने वाला है? अमेरिका के चुनावी नतीजों के पीछे की पूरी राजनैतिक कहानी क्या है और आने वाले दिनों में ट्रंप के सामने कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। आज का एमआरआई इसी पर करेंगे।

ट्रंप की पार्टी को झटका लेकिन राष्ट्रपति की सफाई पहले से आ गई। अमेरिका में मंगलवार को मिड टर्म चुनाव संपन्न हुए। इन चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर



पद के लिए भी चुनाव कराए गए।सीनेट में भी डेमोक्रेट्स की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दी। यानी जिस अमेरिकी संसद में ट्रंप अपनी पार्टी के समर्थन के सहारे बड़े फैसले लेने की उम्मीद कर रहे थे, वहां अब विपक्ष की ताकत बढ़ती हुई नजर आई। और इसी बीच ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वह खुद चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे। अगर वह उम्मीदवार होते तो उनकी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतती। अब जरा इस बयान के राजनीतिक मायने समझिए। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप लगातार रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे कि उम्मीदवारों को वोट देते समय उन्हें यानी ट्रंप को ध्यान में रखें। लेकिन जैसे ही नतीजों में पार्टी पिछड़ती दिखाई दी ट्रंप ने सफाई देना शुरू कर दिया कि वह खुद बैलेट पर मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद रखते हैं। यानी एक तरफ चुनावी हार की जिम्मेदारी से दूरी बनाने वाला बयान और दूसरी तरफ विपक्ष के साथ काम करने की बात।

ट्रंप के सामने पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा महाभियोग यानी इंपीचमेंट हो सकता है। अमेरिका के या अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति प्रतिनिधि सभा के पास होती है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेती है तो उसके पास ट्रंप प्रशासन के फैसलों को और उसकी नीतियों की जांच करने को महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को एक अवसर मिल सकता है। और यहां एक दिलचस्प बात है डॉनल्ड ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में भी दो बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं। ऐसे में अगर दूसरे कार्यकाल में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह उनके राजनैतिक भविष्य के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव पास होने का मतलब राष्ट्रपति को तुरंत पद से हटाना नहीं होता। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सेनेट में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होना भी किसी राष्ट्रपति के लिए छोटी बात नहीं है। इसका मतलब होगा कि ट्रंप को अपने प्रशासन का बचाव करना पड़ेगा। विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और राजनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसी लड़ाई में खर्च करना पड़ सकता है। यानी जिस राष्ट्रपति का एजेंडा देश की नीतियों को बदलने का हो उसे अपने कार्यकाल की राजनीतिक बचाव में बिताना पड़ सकता है।

अब बात करते हैं उस दूसरे खतरे की। मान लीजिए कि ट्रंप कोई बड़ा कानून बनाना चाहते हैं। टैक्स में कटौती करना है, आवरजन नियमों को सख्त करना है या अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव लाना है। लेकिन अगर संसद के एक या दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण हो गया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को लागू करना काफी मुश्किल होगा। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास असीमित अधिकार नहीं होते। संसद की मंजूरी भी कई बड़े फैसलों के लिए जरूरी होती है। अगर विपक्षी पार्टी संसद में मजबूत हो जाती है तो वह ट्रंप के प्रस्तावित कानूनों को रोक सकती है। उनमें बदलाव की मांग कर सकती है या उन्हें मंजूरी देने में देरी कर सकती है। इसी स्थिति को राजनीतिक भाषा में ग्रिड ललॉक कहा जाता है। यानी सरकार और संसद के बीच ऐसा गतिरोध जिसमें बड़े फैसले आगे नहीं बढ़ पाते और इसका सीधा असर ट्रंप के राजनैतिक एजेंडे पर पड़ सकता है।

सीनेट वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजदूतों और संघीय न्यायाधीशों (जिनमें सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित लोग भी शामिल हैं) की नियुक्ति की पुष्टि करती है। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली सीनेट ट्रम्प द्वारा नामित लोगों की पुष्टि में देरी कर सकती है या उन्हें खारिज कर सकती है। इससे ट्रम्प के लिए अहम पदों को भरना और न्यायपालिका को अपनी पसंद के अनुसार ढालना मुश्किल हो जाएगा। ट्रम्प द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित लोगों को रिपब्लिकन पार्टी (लब्बक) के नियंत्रण वाली सीनेट ने मंजूरी दी थी। असल में हाल के सभी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की पुष्टि उस सीनेट ने की है, जिस पर उसी पार्टी का नियंत्रण था जिससे राष्ट्रपति जुड़े थे। पिछली बार जब विपक्षी दल के नियंत्रण वाली सीनेट ने किसी उम्मीदवार को मंजूरी दी थी, तो वह 1991 की बात है।

अमेरिका में सरकारी खर्च पर कांग्रेस का नियंत्रण होता है। डेमोक्रेट्स, ट्रंप की प्राथमिकताओं के लिए फंडिंग को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। इससे बजट को लेकर लंबी बातचीत शुरू हो सकती है और नौबत सरकारी कामकाज ठप होने (गवर्नमेंट शटडाउन) तक भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास व्हाइट हाउस का नियंत्रण नहीं होता, वह अक्सर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करती है, जिसमें %डेट-सीलिंग% (कर्ज की सीमा) बढ़ाने जैसी बातें शामिल हैं ताकि वह बहुमत वाली पार्टी से अपनी शर्तें मनवा सके।

संसद (कांग्रेस) के समर्थन के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां मौजूद रहेंगी। वे कांग्रेस की विधायी मंजूरी के बिना भी कई बड़े नीतिगत फैसले कार्यकारी आदेशों (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स) के जरिए ले सकते हैं।

आज का इतिहास

1858 अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल का जन्म।
1862 मुग़ल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत।
1867 रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैरी क्यूरी का जन्म। वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हैं। वह ऐसी पहली शख्सियत और एकमात्र महिला हैं जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
1876 बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतल पाडा नामक गाँव में वन्दे मातरम् गीत की रचना की थी।
1888 भारत के महान भौतिक शास्त्री सी वी रमन का जन्म। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1917 रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति।
1951 जार्डन में संविधान पारित किया गया।
1968 तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।
1996 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया।
1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की। दुनिया का सबसे बुजर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटा।
2000 अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान सम्पन्न।
2002 अमेरिकी सीनेट के लिए हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला, आयरलैंड के रिचर्ड डोनोवाल 12वीं हिमालय रन एंड ट्रेक स्पर्धा में पुरुष वर्ग के चैम्पियन बने। ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया।
2003 अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने गर्भपात पर रोक सम्बन्धी विधेयक पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा वापस ली।
2005 पाकिस्तान और अमेरिका एफ़-16 विमान टालने पर सहमत हुए। फ़्रांस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ़ फतवा जारी किया।
2006 भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फ़ंड बनाने पर सहमत हुए।
2008 बिहार के जनतादल (यूनाइटेड) के लोकसभा सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
2012 ग्वाटेमाला में भूकंप, 52 की मौत।
2021 ड्रोन हमले में बाल-बाल बचे इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा

यूपी में भाजपा की पदयात्रा का मेगा प्लान के राजनीतिक निहितार्थ

कमलेश पांडे

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा नीत राजग (एनडीए) और कांग्रेस नीत इंडी गठबंधन का मजबूत साथी समाजवादी पार्टी के बीच कौंटे की टक्कर के आसार हैं! भाजपा भले ही दलितों और ओबीसी को पटाने के चक्कर में सवर्णों की सरजमीनी नाराजगी मोल ले चुकी है, जबकि समाजवादी नेता व उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक (पीडीए) वोटरों को अपनी ओर खींचकर और कांग्रेस को साथ लेकर लोकसभा चुनाव 2024 और विधान परिषद चुनाव 2026 में भाजपा को अपनी मजबूत राजनीतिक ताकत का एहसास करवा चुके हैं।

ऐसे में यूपी के सवर्ण वोटर यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ के सुशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए भाजपा से जुड़े रहते हैं तो भाजपा मुकाबले में रहेगी, अन्यथा दलित और ओबीसी कानूनों को मजबूत करने और पूंजीवादी राज को प्रश्रय देने की कीमत उसे अपनी राज्य और केंद्र की सत्ता (2029) गंवा कर चुकानी पड़ेगी, जबकि भाजपा किसी भी कीमत पर यूपी की सत्ता गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने के लिए नई रणनीति बनाई है?

भाजपा की यह पदयात्रा महज जनसंपर्क अभियान नहीं है बल्कि इसके पीछे उसकी संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष की घेराबंदी और चुनावी मुद्दों की दिशा तय करने की व्यापक कोशिश भी है। यदि भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के मतभेद को काबू में करने में सफल हो जाती है तो लखनऊ में उसकी तीसरी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि वह कैडर बेस पार्टी है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा के मेगा प्लान में बड़े बड़े नेताओं को लगाना इन्हीं राजनीतिक संदर्भों में समझना चाहिए। यह अभियान ऐसे समय हो रहा है, जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और भाजपा तथा विपक्ष के बीच चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक विरोध के तौर-तरीकों को लेकर गंभीर बहस चल रही है।

सबसे पहले जानिए कि आखिर पदयात्रा का कार्यक्रम क्या है? प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने 3 से 5 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं आयोजित करने की योजना बनाई है। इसका घोषित उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। इस सिलसिले में निर्धारित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं- तारीख, स्थान और प्रमुख नेतृत्व- 3 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा की और वोटरों के मूड को बदलने का सकारात्मक प्रयास किया। वहीं, 3 नवंबर को ही बरेली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पदयात्रा की और वोटरों के मूड को समझने की सफल कोशिश की। वहीं, 4 नवंबर को गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदयात्रा करेंगे। वहीं, 4 नवंबर को ही प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पदयात्रा करेंगे। वहीं, 4 नवंबर को ही कानपुर में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पदयात्रा करेंगे। वहीं, 5 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा होगी।

तीन नवंबर को लखनऊ में लोकभवन से परिवर्तन चौक तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पार्टी ने इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी का लक्ष्य रखा और उसे पूरा किया।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने की भाजपा की रणनीति कितनी जबर्दस्त है? इस पदयात्रा का पहला राजनीतिक निहितार्थ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना



है, क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। जबकि भाजपा का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ जैसा दूरगामी असर वाला राजनीतिक संदेश चुना है। इसका अर्थ है कि पार्टी बहस को विपक्ष के आरोपों से हटाकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक आचरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उसके रवैये पर केंद्रित करना चाहती है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों का जवाब केवल राजनीतिक सभाओं से नहीं, बल्कि पारदर्शी तथ्यों और संस्थागत जवाबदेही से भी देना आवश्यक होगा।

तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर एसआईआर और मतदाता सूची की बहस का राजनीतिक महत्व क्या है? इस अभियान के पीछे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ट्रक्र) भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस मुद्दे पर दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने हैं- एक, भाजपा का पक्ष: मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। पार्टी इस प्रक्रिया के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना चाहती है। दो, विपक्ष का पक्ष: मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने, पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं उठाई जा रही हैं। यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता, उचित सूचना और आपत्ति दर्ज कराने के प्रभावी अवसर के साथ हो रहा है? लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना भी है। इसलिए पदयात्रा के राजनीतिक संदेश के साथ-साथ एसआईआर पर तथ्यात्मक संवाद भी इस अभियान की कसौटी रहेगा।

चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक भूमिका और नेतृत्व का प्रदर्शन कैसा रहेगा? इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय भागीदारी के कई राजनीतिक पहलू हैं। एक, सरकार और संगठन के बीच तालमेल का प्रदर्शन- मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के प्रमुख नेताओं की भागीदारी से अभियान को राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर महत्व मिलता है। दो, नेतृत्व की सार्वजनिक सक्रियता- पदयात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सीधे कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों के बीच उपस्थित होते हैं। इससे चुनाव से पहले संगठनात्मक संपर्क को सक्रिय रखने का अवसर मिलता है। तीन, 2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि। योगी आदित्यनाथ की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व की राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी इस कार्यक्रम को केवल स्थानीय संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रहने देती।

पांचवां सवाल यह है कि यूपी के छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्रा का क्या संदेश है? इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका भौगोलिक विस्तार है। भाजपा ने केवल लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने के बजाय छह संगठनात्मक क्षेत्रों में अलग-अलग पदयात्राओं की योजना बनाई है। इसके तीन संभावित संगठनात्मक उद्देश्य हैं: एक, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना- स्थानीय इकाइयों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारी के लिए सक्रिय रखना। दो, स्थानीय संपर्क बढ़ाना- व्यापारियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों तक पहुंच बनाना। तीन, एक समान राजनीतिक संदेश- प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही नारे और राजनीतिक मुद्दे को सामने रखना। भाजपा की तैयारियों में सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

छठा प्रासंगिक सवाल यह है कि विपक्ष के सामने क्या राजनीतिक चुनौतियां हैं? इस अभियान से विपक्ष के सामने भी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। एक, क्या विपक्ष मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया पर अपने आरोपों को ठोस प्रमाणों के साथ जनता के सामने रख पाएगा? दो, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन मुद्दों पर एक साझा राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे? तीन, क्या विपक्ष केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रहेगा या रोजगार, महंगाई, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी समान महत्व देगा? चार, क्या विपक्ष भाजपा के इस अभियान के जवाब में जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए प्रभावी जनसंपर्क कर पाएगा? यहां एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक तथ्य भी समझना चाहिए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना और चुनावी संस्थाओं से सवाल पूछना अपने आप में अराजकता नहीं है। उसी तरह शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। किसी भी पक्ष के आरोपों और दावों का मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

सातवां सवाल है कि आखिर भाजपा के लिए असली परीक्षा क्या होगी? पदयात्रा में कितनी भीड़ जुटती है, कितने बड़े नेता शामिल होते हैं और कितने स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, ये सभी संगठनात्मक गतिविधि के मापदंड हो सकते हैं।

राहुल गांधी का बढ़ता आत्मविश्वास क्या कोई राजनीतिक संदेश है?

सौरभ वार्ष्णेय

देशभक्ति किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की बपौती नहीं है। यह संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रति नागरिकों की निष्ठा से जुड़ी भावना है। फिर आखिर देशभक्ति को लेकर राजनीतिक तकरार क्यों ? क्या राष्ट्रप्रेम का प्रमाण एक-दूसरे पर आरोप लगाकर और बहस की चुनौती देकर दिया जाएगा? भारतीय राजनीति में इन दिनों जिस तरह बयानबाजी और कटाक्ष का दौर तेज हुआ है, उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बदला हुआ राजनीतिक तेवर विशेष चर्चा का विषय बन गया है। देश में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर विपक्षी आंदोलन शुरू होने के बाद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री को सीधे बहस की चुनौती देकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। राजनीति में एक-दूसरे पर कटाक्ष करना और सवाल उठाना नई बात नहीं है, लेकिन आंदोलन के बीच राहुल गांधी का इस तरह आत्मविश्वास के साथ सामने आना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। सवाल है कि क्या यह केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक शैली में बदलाव है या विपक्ष की बदलती रणनीति का हिस्सा? दरअसल, राहुल गांधी लंबे समय से अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता को लेकर उठते सवालों का सामना करते रहे हैं। लेकिन अब उनका आक्रामक अंदाज, सरकार से सीधे सवाल और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार हमले यह संकेत दे रहे हैं कि वह विपक्ष की राजनीति में अपनी भूमिका को नए सिरे से स्थापित करना चाहते हैं। वोट चोरी का मुद्दा उनके लिए केवल चुनावी आरोप नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों से जुड़ा ऐसा विषय बन गया है, जिसके सहारे कांग्रेस विपक्षी दलों को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के बढ़ते आत्मविश्वास के पीछे बदलता राजनीतिक माहौल भी एक कारण हो सकता है। जिस तरह उनके समर्थन में विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता दिखाई दे रही है, उससे कांग्रेस को उम्मीद बंधी है कि वह इस मुद्दे को व्यापक जनआंदोलन का रूप दे सकती है। हालांकि, किसी नेता के पक्ष में बनता राजनीतिक माहौल स्थायी जनसमर्थन का प्रमाण नहीं होता। उसे चुनावी परिणामों और जनता के वास्तविक विश्वास की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब केवल सरकार की आलोचना करने वाले नेता की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती देना भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बहस किस मुद्दे पर होगी? क्या देश को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बहस चाहिए या चुनाव सुधार, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर गंभीर संवाद की आवश्यकता है? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच नीतिगत बहस निश्चित रूप से स्वस्थ परंपरा हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को तथ्यों और तर्कों के साथ सामने आना होगा। केवल चुनौती देना और उसे राजनीतिक सुर्खियों में बदल देना जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। यहां देशभक्ति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सरकार की आलोचना करना देश का विरोध करना नहीं है और सरकार का समर्थन करना ही राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं हो सकता।

बिहार भाजपा की सदस्यता की रसीद या विधान पार्षद दल-बदल का सबूत?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बिहार विधान परिषद के चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने राजनीतिक समीकरणों को चौंका दिया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, जबकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राहुल राज निर्वाचित हुए। दोनों ने एनडीए के सहयोगी जदयू के उम्मीदवारों को हराया था।

राहुल राज की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। वह पहले भाजपा से जुड़े रहे थे। गठबंधन में सारण शिक्षक सीट जदयू के खाते में जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बंशीधर ब्रजवासी भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी सीट बचाने में सफल रहे।

लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोनों की राजनीतिक दिशा बदलती दिखाई दी। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों पहुंचे। भाजपा का पट्टा पहना और सदस्यता की रसीद हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाई। सवाल है कि जब चुनाव निर्दलीय लड़कर जीता था तो फिर भाजपा की सदस्यता लेने की जरूरत क्यों पड़ी?

इस पूरे विवाद में सबसे अहम है सामने आई तस्वीर। दोनों नेताओं के गले में भाजपा का पट्टा है और हाथों में पार्टी की सदस्यता की रसीद। यह कोई सामान्य मुलाकात या शिष्टाचार भेंट की तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर खुद कई सवाल खड़े करती है। मामला तब और गंभीर हो गया जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की ओर से भी दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने का संदेश सामने आया। बाद में इस संदेश में बदलाव किए जाने की खबरें



आईं। बंशीधर ब्रजवासी ने पहले भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन विवाद बढ़ने पर अपना रुख बदल लिया। उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली, बल्कि सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। राहुल राज के मामले में भी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने और समर्थन देने के बीच अंतर को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।

अब सवाल यह है कि यदि केवल समर्थन देना था तो सदस्यता की रसीद क्यों बनी? पार्टी के कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण करने का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों हुआ? प्रदेश अध्यक्ष के संदेश में दोनों को पार्टी में शामिल बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या राजनीतिक विवाद खड़ा होने के बाद सदस्यता को समर्थन का नाम दिया जा रहा है? क्या तस्वीर और रसीद की राजनीतिक जिम्मेदारी से बचा जा सकता है?

इस विवाद का सबसे गंभीर पहलू संविधान की दसवीं अनुसूची है। इसके पैरा 2(2) में प्रावधान है कि ऐसा निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में नहीं चुना गया हो, चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो सकता है।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य के लिए छह महीने की कोई छूट नहीं है। छह महीने का प्रावधान निर्दलीय सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में मनोनीत सदस्यों के लिए है। इसलिए राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी के मामले में असली सवाल यही है कि क्या उन्होंने भाजपा की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की थी या केवल सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी? दोनों स्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। कोई निर्दलीय सदस्य सरकार का समर्थन कर सकता है, उसके पक्ष में मतदान कर सकता है और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना अलग मामला है।

संविधान के पैरा 6 के अनुसार अयोग्यता से जुड़े सवाल पर संबंधित सदन के सभापति को निर्णय करना होता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों की सदस्यता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन कानूनी चुनौती को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। भाजपा के इस घटनाक्रम पर राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि भाजपा संविधान और दल-बदल कानून की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी इसे जनादेश के साथ धोखा बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने विधान परिषद के सभापति के सामने शिकायत करने और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। जन सुराज का तर्क है कि मतदाताओं ने दोनों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुना था। चुनाव जीतने के तत्काल बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेना मतदाताओं के फैसले की भावना के विपरीत है। यहां एक सवाल विपक्ष से भी है। क्या राजनीतिक दलों को केवल तब संविधान की याद आती है जब सत्ता पक्ष के किसी कदम से उन्हें राजनीतिक लाभ दिखाई देता है? क्या यही कसौटी विपक्षी दलों के नेताओं पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए?फिर भी, इस मामले में कानूनी प्रावधान को राजनीतिक आरोप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।

इस घटनाक्रम का एक दूसरा राजनीतिक पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने चुनाव में भाजपा के सहयोगी जदयू के उम्मीदवारों को हराया था। अब वही दोनों भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल राज की सीट गठबंधन में जदयू के हिस्से आई थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की। बंशीधर ब्रजवासी ने भी जदयू उम्मीदवार को हराया। ऐसे में भाजपा का दोनों नेताओं को अपने साथ खड़ा करना क्या केवल राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश है या गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का कोई नया खेल? जदयू के लिए भी यह असहज स्थिति है। उसके उम्मीदवारों को हराने वाले निर्दलीय अब उसी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की राह में अब कांटे ही कांटे?

राजेश बादल

जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह अपने आलेख में लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मध्यावधि चुनाव में विजय हासिल करना आसान नहीं है। वही हुआ। उन्होंने जबर्दस्त पटखनी खाई और खुद को लहूलुहान कर लिया। अब वे एक ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं, जो दुनिया में सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है लेकिन अपने ही घर में वह एक थका-हारा मुखिया है।

अब उस मुखिया की अपने ही मुल्क में मनमर्जी नहीं चलेगी। उसे अपनी बात मनवाने के लिए प्रतिपक्ष के सामने कदम-कदम पर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मध्यावधि चुनाव में प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और सीनेट (उच्च सदन) में अब डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है। इसके अलावा गवर्नरों के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी को मुंह की खानी है।

यह ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब छवि के सहारे वे अपने पसंदीदा चेहरों को भी जिताने में नाकाम रहे हैं। इस कारण खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि चूंकि वे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी हार गई। उनके इस बयान से पार्टी बिफरी हुई है।

जिस पार्टी ने पहली बार डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तब तो ट्रम्प के यश खाते में अपनी कोई पूंजी ही नहीं थी। रिपब्लिकन पार्टी ने ही उन्हें विजय दिलाकर व्हाइट हाउस में भेजा



था। अब वे हार का ठीकरा उसी पार्टी पर फोड़ रहे हैं। वे अपनी सरकार की नीतियों में खामियां और उनके दुष्परिणामों को नहीं देख रहे हैं और न ही शिखर पदों पर अयोग्य व्यक्तियों के चयन को स्वीकार कर रहे हैं।

इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में उनके दंभ और झूठे बयान भी चुनाव में पराजय की बड़ी वजह हैं। देश का संविधान लोकतंत्र समर्थक है और डोनाल्ड ट्रम्प मिजाज से अलोकतांत्रिक हैं। संविधान और स्वभाव के इस बेमेल गठबंधन का नुकसान मतदाताओं को उठाना ही था। इसी कारण उन्होंने पिछले चुनाव में राष्ट्रपति के लिए गलत आदमी को चुनकर जो भूल की थी, मध्यावधि चुनाव में उन्होंने सुधार ली है।

अमेरिकी मतदाताओं को इस नजरिये से अपने संविधान निर्माताओं का आभारी होना चाहिए कि वह भूल सुधार का अवसर अपने मतदाता को देता है। यह लोकतांत्रिक सेहत के लिए निश्चित रूप से उम्दा माना जाना चाहिए। अन्यथा एक बार पद पर बैठने के बाद राजनेता खुद को महाराजा से कम नहीं समझते। मैंने इसी पन्ने पर एक आलेख में लिखा था कि पूंजी और लोकतंत्र में बुनियादी रंजिश है।

जब कोई पूंजीपति धनबल से चुनाव जीतना चाहता है, तो वह केवल नफा-नुकसान की भाषा समझता है। इससे आम जनता का भला नहीं होता। उसके लिए जरूरी शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मसले हाशिये पर चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प इस मायने में कामयाब नहीं रहे हैं। दरअसल अमेरिका फर्स्ट का नारा खालिस अमेरिकी मूल के दक्षिणपंथी मतदाताओं पर तो असर डाल सकता था, लेकिन ट्रम्प भूल गए कि उनके देश में अखिल विश्व के लोग आकर बसे हैं। इस नारे ने उनके दिल की गहराइयों तक असर नहीं डाला।

शायद यह कुछ प्रभाव डालता बशर्ते आम नागरिक को बेरोजगारी और महंगाई से नहीं जूझना पड़ता, देश को आर्थिक बदहाली के दौर से नहीं गुजरना पड़ता और मित्र देशों से अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट नहीं आई होती। अमेरिकी वोटरों में बड़ी आबादी उसके मित्र और शुभचिंतक राष्ट्रों से आकर बसे लोगों की है।

वे आधुनिक-उदार समाज की नुमाइंदगी करने वाले देश अमेरिका को पसंद करते थे, कट्टर और सनकी प्रशासन को नहीं। अरसे से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हथकड़ी-बेड़ी डालकर अपमानित कर उनके मुल्क में वापस भेजने से उन देशों के मूल निवासियों का स्वाभिमान आहत हुआ। इसके अलावा ट्रम्प सरकार ने अस्थिरता की तलवार उन पर लटकाए रखी।

आप्रवासियों पर रोजगार का संकट पैदा किया गया। इस तरह वे ट्रम्प की पार्टी से छिटकते गए। वैसे अमेरिका में किसी राष्ट्रपति के लिए मध्यावधि चुनाव में हारना कोई अप्रत्याशित नहीं है। अधिकांश राष्ट्रपतियों की पार्टियां मध्यावधि चुनाव में हार चुकी हैं। कह सकते हैं कि मध्यावधि चुनाव में पराजय की इस देश में लंबी परंपरा रही है।

लेकिन किसी अन्य राष्ट्रपति ने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा इतनी नहीं गिराई। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प की पराजय अपेक्षाकृत अधिक शर्मनाक है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि ट्रम्प की छवि वहां निरंतर बदलते रहने वाले फैसलों और दोषपूर्ण रक्षा, विदेश, औद्योगिक और आंतरिक नीतियों के चलते लगातार गिरी है।

उनकी साख धूमिल हुई है और वे देश की समस्याओं का समाधान खोजने में असफल रहे हैं। जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात है तो मध्यावधि के बाद ट्रम्प को भारत के बारे में रवैया बदलना होगा। अभी वे भारत विरोधी दिखाई देते हैं। वैसे तो अमेरिकी नीति हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रही है।

इस कारण भारत ने भी संसार के इस सबसे शक्तिशाली देश से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं लगा रखी हैं। रूस और ईरान से भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। ट्रम्प ने इन संबंधों की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। आशा करें कि इस पराजय से ट्रम्प सबक लेंगे और भारत के हितों को ध्यान में रखेंगे।

दिवाली से पहले डीआरडीओ ने टेस्ट किया सबसे बड़ा पटाखा

नीरज कुमार दुबे

दिवाली से पहले भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ऐसा पटाखा टेस्ट किया है, जिसकी आवाज दुश्मन देशों तक पहुंच गई है। यह पटाखा कोई आम आतिशबाजी नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी प्रलय मिसाइल है। 5 नवंबर को ओडिशा तट के पास इस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। खास बात यह है कि यह परीक्षण केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारतीय सेना में प्रलय मिसाइल को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। देखा जाये तो भारत अब ऐसी मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन के सैन्य ठिकानों, एयरबेस, कमांड सेंटर और हथियारों के भंडार को निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं। हम आपको बता दें कि प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह पारंपरिक विस्फोटक वारहेड ले जाने में सक्षम है और अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यों के हिसाब से इसके पेलोड में बदलाव किया जा सकता है। इसकी पेलोड क्षमता लगभग 350 से 1,000 किलोग्राम तक बताई जाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी उड़ान का तरीका है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक निश्चित घुमावदार रास्ते पर चलती हैं, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए उनकी दिशा का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन प्रलय उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और जरूरत के मुताबिक दिशा में बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि इसे इंटरसेप्ट करना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठोस ईंधन से चलने वाली यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और तेजी से तैनात करना आसान होता है। साथ ही इसका परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुरुआती विकास परीक्षण नहीं, बल्कि सेना की जरूरतों के मुताबिक किए जा रहे यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, परीक्षण के सभी निर्धारित उद्देश्य पूरे हुए। डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे विकसित किया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसका उत्पादन किया है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस सफल परीक्षण के बाद मिसाइल को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया अब बेहद करीब है। इसका अर्थ है कि भारत अब केवल मिसाइल विकसित करने के चरण में नहीं है, बल्कि उसे वास्तविक सैन्य इस्तेमाल के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रलय की तैनाती से भारत की पारंपरिक मिसाइल मारक क्षमता में बड़ा बदलाव आ सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल सीमा के भीतर स्थित एयरबेस, सैन्य ठिकानों, हथियारों के डिपो, रडार प्रतिष्ठानों और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का महत्वपूर्ण हथियार बन सकती है। इसकी 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को इसकी जद में ला सकती है।



मस्तिष्क में प्रोटीन के गुच्छे बनने से घटती है याददाश्त

साइंस एडवांसेस में प्रकाशित जॉर्ज मिसल और उनके सहकर्मियों के शोध में अल्जाइमर रोगियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस तरह से अनुसंधानकर्ता मस्तिष्क में अल्जाइमर बीमारी के बढ़ने को रोकने की प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ बनाने में सक्षम हुए।

गुच्छों के दोगुना होने में पांच साल का समय लगा

अध्ययन से पता चला कि गुच्छों के दोगुना होने में करीब पांच साल का समय लगा। अध्ययन में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशों के बीच यात्रा रोकना बेहद प्रभावी कदम नहीं हो सकता है जब मूल देश में पहले से ही उल्लेखनीय रूप से संक्रमित लोगों की मौजूदगी पहले से ही हो। इसी तरह से मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच गुच्छों के प्रसार को रोकना अल्जाइमर के एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे धीमा करने में नाकाफी हो सकता है।

दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अल्जाइमर और अन्य तरह की डिमेंशिया से प्रभावित हैं लेकिन दुनिया में इसका प्रभावी इलाज के संबंध में प्रगति धीमी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मरीज के मस्तिष्क में अल्जाइमर से संबंधित प्रोटीन गुच्छे के रूप में जमा होने लगते हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं और स्मृति लोप होने संबंधी लक्षण दिखने लगते हैं।

घीरे-धीरे बढ़ती जाती है गुच्छों की संख्या

अल्जाइमर की बीमारी और तंत्रिका तंत्र से संबंधित अन्य बीमारियों में प्रोटीन, वे सूक्ष्म गुच्छों में एकसाथ चिपकने लगते हैं। मरीज के मस्तिष्क में ये गुच्छे के रूप में जमा होने लगते हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं और स्मृति लोप होने संबंधी लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे-जैसे इन गुच्छों की संख्या बढ़ती जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है और हल्के लक्षण सामने आने के वर्षों बाद मौत तक हो जाती है। अब तक विस्तार से वैज्ञानिकों के हाथ यह जानकारी नहीं लग पाई है कि आखिर ये गुच्छे बन कैसे जाते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।



सुपरफूड है अंडा
कई बीमारियों से बचाता है

अंडा एक ऐसा सुपरफूड है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड विटामिन ए और बी की भरपूर मात्रा होती है। इसका रोजाना सेवन शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वहीं हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार रोजाना 1 अंडा खाने से डायबिटीज का खतरा कम होता है।

टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम करता है अंडा

इस स्टडी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई दूसरे वैज्ञानिक इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि डायबिटीज में अंडा खाने को लेकर शोधकर्ताओं की राय अलग-अलग है। जहां कुछ वैज्ञानिक इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं वहीं अन्य शोधकर्ताओं के हिसाब से डायबिटीज के मरीजों को अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए।

हफ्ते में कितने अंडे खाना है सुरक्षित?

इस नई स्टडी के अनुसार, हफ्ते में 3 अंडे खाना बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपको डायबिटीज है तो अंडे को उबालकर ही खाएं।

फायदेमंद है अंडे का सेवन

जो पुरुष रोजाना अंडे का सेवन करते हैं उनके खून में लिपिड की मात्रा थोड़ी ही पाई जाती है, जिससे इस बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अंडा सेहत को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। फिलहाल अंडा खाने या ना खाना अभी तक शोधकर्ताओं के लिए पहेली ही बना हुआ है। हालांकि इस नई स्टडी के नतीजों में दावा किया है कि रोजाना एक अंडा खाने से डायबिटीज का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है।

कैसे और कब खाना चाहिए अंडा

रोजाना 2 उबले हुए अंडे खाने से शरीर कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। अंडा को ब्रेकफास्ट के रूप में खाने से शरीर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जिम जाने वाले लोगों को कच्चा अंडा दूध में मिलाकर खाना चाहिए। इसके अलावा कच्चे अंडे की जर्दी (एग योक) का सेवन भी आपको कई गंभीर बीमारियों से बचाता है।

व्हाइट या ब्राउन कौन है बेस्ट?

व्हाइट और ब्राउन दोनों ही अंडों पर काफी बार शोध किया जा चुका है, जिसमें इन दोनों में कोई खास अंतर पता नहीं चला। दोनों के फायदे, क्वॉलिटी, आकार सभी कुछ एक जैसा है। यहां तक दोनों में पोषण भी एक जैसा ही होता है लेकिन ब्राउन अंडे में व्हाइट अंडे से थोड़ा ज्यादा ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है।

रोजाना अंडा खाने के अन्य फायदे



मजबूत इम्यून सिस्टम

रोजाना ब्रेकफास्ट में एक अंडा खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत है। इससे आप सर्दी-जुकाम जैसे वायरल इंफेक्शन से बचे रहते हैं।

वजन कंट्रोल

अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोजाना इसका सेवन जरूर करें। इससे दिनभर पेट भरा रहता है, जिससे आप ओवरइटिंग से बच जाते हैं और आपका वजन कंट्रोल में रहता है।

आंखों व दिमाग के लिए फायदेमंद

इसमें कॉलिन और कैरोटिनायड्स नाम का पोषक तत्व होता है, जो आंखे व दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है।

स्वस्थ दिल

इसका सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है और आप हार्ट अट्रैक जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं।

ब्रैस्ट कैंसर से बचाव

अंडे में पाया जाने वाला फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 ब्रैस्ट कैंसर से बचाव करता है। अगर आप भी ब्रैस्ट कैंसर से बचना चाहते हैं तो रोज इसका सेवन करें।





सर्दियों में होंठ और हाथों की यूं करें देखभाल

सर्दियों में होंठ व हाथ रूखे हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। होंठ और हाथों की देखभाल के संबंध में ये सुझाव दिए हैं :

हाथों के लिए सुझाव

हाथ धुलने के बाद मॉइश्चराइजर बरकरार रखने के लिए हमेशा अच्छा हैंड क्रीम लगाएं।
रात में हाथों को अच्छे नरीशिंग क्रीम से मसाज करें और नाखूनों व नाखूनों के आसपास के हिस्से में भी मसाज करना नहीं भूलें।
नहाने से पहले त्वचा पर तेल से मसाज करें। इससे आपके हाथ मुलायम बनेंगे।
नहाने के तुरंत बाद लोशन या क्रीम लगाएं। इससे त्वचा में नमी बरकरार रहेगी।
सर्दियों में शावर जेल या ग्लिसरीन युक्त साबुन का इस्तेमाल करें।
एक बड़े चम्मच एवोकैडो ऑयल में एक बड़ा चम्मच शहद और एक बड़ा चम्मच दही मिला लें और इससे हाथों की मसाज करें। हाथों का रूखापन दूर करने के लिए 10 मिनट बाद धो लें।

होंठ की देखभाल

होंठों को रूखेपन व फटने से बचाने के लिए आर्गन प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की कुछ बूंदों में एक बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर मिलाकर लगाएं।
फटे होंठों के लिए शहद मॉइश्चराइजर का काम करता है। शहद को अपने होंठों पर लगा लें या फिर रात में सोने से पहले शहद और ग्लिसरीन के मिश्रण को लगा लें।
आप चाहे तो ताजे दूध की क्रीम भी होंठों पर लगा सकते हैं और इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर इसे गुनगुने पानी में भीगी रूई के फाहे से हल्के हाथों से साफ कर लें। कोमल व गुलाबी रंगत के होंठों के लिए ऐसा रोजाना करें।
रात में सोने जाने से पहले होंठों को गुनगुने पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछे ले और फिर तुरंत लिप बाम लगा लें।
होंठों की नमी बरकरार रखने के लिए पानी का सेवन खूब करें, इससे आपके होंठों की कोमलता बरकरार रखने में मदद मिलेगी।
सर्दियों में होंठों को फटने से बचाने के लिए ऑर्गेनिक घी, बादाम तेल और नारियल तेल युक्त लिप बाम का इस्तेमाल करें।
सर्दियों में लिपस्टिक आपके होंठों को सुरक्षा प्रदान करता है। पिंक या प्लम कलर के लिपस्टिक लगा सकती हैं, जो आपके होंठों की न सिर्फ खूबसरती बढ़ाएगा, बल्कि इसे कोमल भी रखेगा। ऑर्गेनिक घी, शहद, बादाम तेल, रोज ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स सर्दियों में आपके होंठों को कोमल रखेंगे।
रोजाना हैंडक्रीम लगाने से हाथ रूखे नहीं होंगे। कोकम बटर, ऑर्गेनिक हनी, एलो, हल्दी, सेसम ऑयल, एप्रिकोट ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स अल्ट्रा-मॉइश्चराइजिंग होते हैं, जो त्वचा को मुलायम रखते हैं।
गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी त्वचा को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना जरूरी है। तेज धूप में त्वचा को टैनिंग से बचाने के लिए धूप में निकलने से पहले सन प्रोटेक्शन क्रीम का इस्तेमाल करें।

रोजाना लौंग चबाने से ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी दूर

मसाले खाने को स्वादिष्ट बनाने के ही नहीं बल्कि सेहत से जुड़ीं कई परेशानियों को भी ठीक करते हैं। जैसे, लौंग का इस्तेमाल खाने के साथ चाय को स्वादिष्ट बनाने में भी किया जाता है। लौंग के कई फायदे हैं।

दांत दर्द में राहत

लौंग खाने से दांत का दर्द ठीक होता है। लौंग में दर्द को शांत करने वाले गुण पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके दांत में दर्द हो तो लौंग को अपने दांत के बीच में दबाकर रखें।

इंफेक्शन को दूर करता है

लौंग में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं। जिसका मतलब है कि यह बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीवों से होने वाले संक्रमण से बचाव प्रदान कर सकता है। स्किन पर कहीं इंफेक्शन होने पर गुस जगह पर लौंग का पेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है।

एसिडिटी में राहत

सुबह खाली पेट लौंग के सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। लौंग पाचन एंजाइम के स्राव को बढ़ाते हैं, जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स को रोकने या ठीक करने में कारगर है।

पिंपल्स को ठीक करने में कारगर

आपको अगर ऑयली स्किन की वजह से चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, तो आपको लौंग का पेस्ट एलोवेरा जेल में डालकर पिंपल्स पे लगाना चाहिए। इससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं।

मुंह की बदबू को दूर करें

आपके मुंह से अगर सुबह उठने पर बदबू आती है या मसूड़ों में दर्द रहता है, तो आप रोजाना एक लौंग को अपने मुंह में दबा लें, इससे धीरे-धीरे मुंह से बदबू आनी बन्द हो जाएगी।

पेट का अल्सर

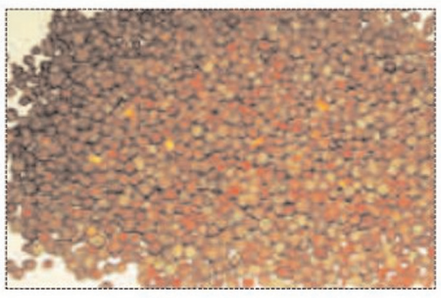
पेट के अल्सर के इलाज में लौंग काफी मदद कर सकता है। यह अल्सर आमतौर पर पेट की सेफ्टी लेयर के कम हो जाने के कारण हो जाते हैं, जिसमें लौंग खाने से फायदा होता है।



छोटी सी राई में कितनी खूबियां

इसकी गिनती सरसों की जाति में होती है। इसका दाना छोटा व काला होता है। राई का प्रमुख गुण पाचक होता है।
पेट के कीड़े इसका पानी पीने से मर जाते है।

हैजे में राई को पीस कर पेट पर लेप करने से उदरशूल व मरोड़ में आराम मिलता है।
इसकी पुल्टिस बना कर दर्द वाली जगह पर सेंक किया जाए तो तुरंत राहत मिलती है। राई के लेप से सूजन कम होती है।
गर्म पानी में राई डालने से राई फूल जाती है। और उसके गुण पानी में पहुंच जाते हैं। इस पानी को गुनगुना सहने योग्य कर किसी टब में कमर तक भर कर बैठा जाए तो सभी प्रकार के यौन रोग प्रदर, प्रमेह आदि में बेहतर सुधार आता है।
इसे पीस कर शहद में मिलाकर सूंघने से जुकाम में आराम मिलता है।



मिर्गी-मूर्च्छा में मात्र राई पीस कर सूंघाने से फायदा होता है।
राई के तेल में बारीक नमक मिलाकर मंजन करने से पायरिया रोग का नाश होता है।
राई के अधिक प्रयोग से उल्टी हो सकती है अत: राई का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए।



सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे गुड़ मेथी के लड्डू

सर्दियों में गुड़ मेथी के लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। गुड़ मेथी के लड्डू ना सिर्फ स्वाद में गजब होते हैं बल्कि इससे इम्यूनिटी बढ़ने के साथ सर्दी भी कम लगती है। जानते हैं, कैसे बनाएं गुड़ मेथी के लड्डू

लड्डू बनाने के लिए सामग्री

100 ग्राम मेथी दाना, 1/2 लीटर दूध
300 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम घी
100 ग्राम गोंद, 30-35 बादाम
300 ग्राम गुड़ या चीनी
8-10 काली मिर्च, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच सोंठ पाउडर, 10 छोटी इलाइची, 4 टुकड़े दालचीनी, 2 जायफल

लड्डू बनाने की विधि

सबसे पहले मेथी दाना को साफ कर लें। अब मेथी को मिक्सर से थोड़ी दरदरी पीस लें।
एक पैन में दूध उबालने के लिए रख दें।
अब पिसी हुई मेथी को 8-10 घंटे के लिए दूध में भिगो दें।
बादाम को काट लें और काली मिर्च, दाल चीनी, इलाइची और जायफल को कूट लें।
अब एक कड़ाही में आधा कप घी डालकर, भीगी हुई मेथी को भूनें. आपको मध्यम आंच पर इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनना है।
अब बचे हुए घी में गोंद को तल लें और किसी प्लेट में निकाल लें।
इसी कड़ाही में बाकी घी डालकर आटे को हल्का ब्राउन होने तक भून लें।
इसके बाद कड़ाही में 1चम्मच घी डाल कर, गुड़ को पिघला लें और चाशनी बना लें।
गुड़ की चाशनी में, जीरा पाउडर, सोंठ पाउडर, कटे हुए बादाम, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और इलाइची डालकर अच्छी तरह मिला लें।
अब इसमें भुनी हुई मेथी, भुना आटा, भुना गोंद डासकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
इस मिश्रण से अपनी पसंद के आकार के लड्डू बनाकर रख लें. लड्डू को थोड़ी देर के लिए हवा में खुला रहने दें।
बाद में किसी एअर टाइट डब्बे में सभी लड्डू को भरकर रख लें।आप इन्हें दूध से रोज सुबह शाम खाएं।
आप चाहें तो लड्डू में गुड़ की जगह पर चीनी या बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने पसंद के हिसाब से लड्डू में कोई मेवा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
मेथी के लड्डू खाने से आपको जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और सर्दी में आराम मिलेगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को आ सकते हैं बिहार

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के वैशाली जिले का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे 1,650 एकड़ में प्रस्तावित एक औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को बताया कि अपने दौरे के दौरान मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह दौरा 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के एक दिन बाद होगा। सरावगी ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। यह कार्यक्रम वैशाली जिले के जाफरपट्टी में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 1,650 एकड़ में एक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बिहार को कई अन्य विकास परियोजनाएं भी मिल सकती हैं।

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के बलात्कार मामले में सुनाई गई 10 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम एम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि वह सजा पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। तेजपाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, हमें नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जिसमें सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। तेजपाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले के सबूतों और अन्य सामग्रियों का हवाला देते हुए दलील दी कि पूरी कहानी झूठी है। गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि इस मामले में सजा बढ़ाई जानी चाहिए। 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को बलात्कार का दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक को पांच साल पहले बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

लोकतंत्र बचाओ अभियान पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को भाजपा के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान की आलोचना की। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह अपने बचाव में विरोध-प्रदर्शन करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में, ठाकरे ने भाजपा को एक अनोखी पार्टी बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी हर स्तर पर सत्ता में है, वह लोकतंत्र बचाने की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन कैसे आयोजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि शायद दुनिया में यह इकलौता ऐसा मामला है, जहां कोई सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में होने के बावजूद, वे लोकतंत्र, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन करते हैं। ठाकरे ने कहा, सत्ता में रहते हुए, वे लोकतंत्र को बचाने के लिए विरोध-प्रदर्शन करेंगे, जबकि असल में वे खुद ही लोकतंत्र का गला घोंट रहे होते हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद का इस्तीफा मंजूर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) से इस्तीफे के बाद लोकसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र 03 नवंबर, 2026 से स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई है। पार्टी छोड़ते समय रुहुल्ला ने सीएम उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं, वह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आवाम के लिए भी दुख का सबब बन चुकी है। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उमर को अपनी टोपी और वकार दूसरों के कदमों में रखने की जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे खुदा से दुआ करते हैं कि सत्ता के लिए उन्हें कभी इतनी लाचारी न देखनी पड़े कि अपनी टोपी ही फेंकनी पड़े। रूहुल्ला ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर असली इज्जत और स्वाभिमान देखना है तो बडगाम आकर देखा जाए।

अमेरिकी चुनाव नतीजों पर पी. चिदंबरम का तंज

नई दिल्ली। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इन चुनावों में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की जीत हुई है। चिदंबरम ने कहा कि इससे उन सभी लोगों को सबक लेना चाहिए, जो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश का नागरिक बनना चाहते हैं। चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका में चुनाव के दौरान अवैध प्रवास, एशियाई और लैटिन अमेरिकी लोगों के कथित अतिक्रमण और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों पर काफी शोर मचाया गया। इन मुद्दों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, ईंधन की कीमतों और कानून-व्यवस्था जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दे पीछे छूटने का खतरा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि आखिरकार उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के साथ अमेरिका की बुनियादी लोकतांत्रिक समझ और भावना की जीत हुई। उन्होंने कहा, एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश का नागरिक बनना चाहने वाले सभी लोगों के लिए इसमें एक सबक है।

उत्तराखंड गठन रोकने के लिए कांग्रेस और सपा ने किए थे अत्याचार : शाह

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के गठन का विरोध करने और राज्य बनने के आंदोलन के दौरान वहां के लोगों पर अत्याचार करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) की आलोचना की। राज्य के 26वें स्थापना दिवस से पहले, 6 नवंबर को देहरादून में बोलते हुए, शाह ने आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने पहाड़ी राज्य के गठन को रोकने की कोशिश में कई युवाओं की जान ले ली। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य बनाकर राज्य के दर्जे की मांग को पूरा किया था। उन्होंने इस संघर्ष के दौरान हुई रामपुर तिराहा गोलीबारी जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के गठन के लंबे संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई। यह आंदोलन रामपुर तिराहा सहित कई जगहों पर फैला हुआ था।

बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास के विजन पर जोर देते हुए, शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड भारत का पहला पूरी तरह से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह %विकसित भारत 2047% के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गठन में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे हम %विकसित भारत% की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को गर्व, उपलब्धि और संकल्प के प्रतीक के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि 2047 तक %विकसित भारत% के सफर में, %देवभूमि% उत्तराखंड विकसित राज्य का दर्जा पाने वाला पहला राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया विरोध-प्रदर्शनों की आलोचना की।



उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता रचनात्मक बातचीत करने के बजाय, अपने राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं को उकसा रहे हैं। धामी ने कहा, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से, उत्तराखंड आज कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, उद्योग और स्वरोजगार जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ राजनीतिक ताकतें विकास पर सार्थक चर्चा करने के बजाय, भ्रम और टकराव का माहौल बनाने में लगी हुई हैं।

उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रति दिखाए गए अनादर की निंदा की। साथ ही, उन्होंने अखिलेश यादव पर उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहने का आरोप लगाते हुए कहा, उनके लिए उत्तराखंड के सम्मान, गरिमा और आत्म-सम्मान का कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए उनका गठबंधन ही पहली प्राथमिकता है। देहरादून में छात्रों के एक कार्यक्रम के दौरान भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी का खंडन करते हुए, धामी ने इन दावों को झूठ का पुलिंदा बताया और अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, अकेले उत्तराखंड में, हमने नकल कराने में शामिल 100 से अधिक माफिया सदस्यों को जेल भेजा है। इसके अलावा, 35,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल, बिना किसी भ्रष्टाचार और बिना किसी पर्ची-खर्ची (सिफारिश या रिश्वत) के की गई हैं।

फारूक अब्दुल्ला ने 15 असंतुष्ट विधायकों संग की बैठक

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेतृत्व ने शुक्रवार को यहां विधायकों के एक समूह के साथ बैठक के बाद एकजुटता का प्रदर्शन किया और जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया। नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की टूट की अटकलों को ''निराधार अफवाह'' बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है तथा ''कभी नहीं टूटेगी।'' नेकां नेतृत्व ने शुक्रवार सुबह यह बैठक मंत्रिपरिषद में शामिल न किए जाने से कथित तौर पर असंतुष्ट पार्टी विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए आयोजित की थी।



बैठक के लिए पार्टी के लगभग 15 विधायक यहां गुपकार स्थित अब्दुल्ला परिवार के आवास पर पहुंचे थे। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सभी 15 विधायक की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा, ''बिना आधार यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुटों में बंट गई है, जो पूरी तरह से गलत है।''

अब्दुल्ला ने कहा, ''यह पार्टी एकजुट और संगठित है। और जो लोग सोचते हैं कि वे इस पार्टी को रोक सकते हैं तो यह पार्टी न तो कभी टूटी है और न ही कभी टूटेगी, इंशाल्लाह।'' उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने असंतुष्ट विधायकों से बात की। ''उनकी चिंताएं वाजिब हैं, और उन पर बहुत गहराई से विचार किया गया। सभी की बात सुनी गई।'' उन्होंने कहा, ''इंशाल्लाह, पार्टी और सरकार को मजबूत करने के लिए कुछ कदम तुरंत उठाए जाएंगे, जबकि अन्य कदम धीरे-धीरे उठाए जाएंगे।'' नेकां अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई के साथ-साथ ''अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए संघर्ष जारी रहेगा... और इसे इसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाएगा।''

राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

वोट चोरी के बाद अब हक की चोरी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर चुनाव में धांधली और लोगों के मतदान के अधिकार छीनने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के उस बयान पर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान अब आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी कार्ड से की जाएगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के मंत्री का एलान- योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर आईडी से तय होगा। साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए। एसआईआर के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं - रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे। ज्यादातर नाम किनके? जो भाजपा के खिलाफ आक्रोश में हैं।

राहुल ने आगे लिखा कि, वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए, मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी भाजपा के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है। तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें



बहुमत हमेशा भाजपा का हो - और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।

कल जिसने भी ठाना कि भाजपा को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा। नाम कटा - वोट गया। वोट गया - हक गया।

राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, देखते ही देखते आप एक अपहृत लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे, जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।

आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण? यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है। वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी गरीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की गुलाम नहीं हो सकती। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं - ये हक चोरी है। हम ये होने नहीं देंगे।

भाजपा का कांग्रेस से सवाल क्या सोनिया ने की वोट चोरी?

- कहा- संपथ के कार्यकाल में एनडीए को मिली ज्यादा जीत

नई दिल्ली। भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनावों में एनडीए की जीत की दर, वीएस संपथ के सीईसी रहने के दौरान की जीत की दर से कम है। साथ ही, भाजपा ने सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी अपनी विरोधी पार्टी (भाजपा) के लिए वोट चोरी कर रही थीं?

एक्स पर एक पोस्ट में, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि वीएस संपथ को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासनकाल के दौरान सीईसी नियुक्त किया गया था। संपथ ने 11 जून, 2012 से 15 जनवरी, 2015 तक 18वें सीईसी के रूप में काम किया।

भंडारी ने बताया कि सीईसी के रूप में संपथ के कार्यकाल में हुए चुनावों में से एनडीए ने 75 प्रतिशत चुनाव जीते थे। वहीं, सीईसी के रूप में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में एनडीए ने लगभग 66



प्रतिशत चुनाव जीते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, सीईसी के रूप में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में एनडीए की जीत की दर वीएस संपथ के कार्यकाल की तुलना में कम है।

उन्होंने सवाल किया, तो क्या राहुल गांधी के तेज दिमाग के हिसाब से, सोनिया गांधी भाजपा के लिए वोट चोरी कर रही थीं? उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का दावा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में एनडीए को फायदा पहुंचाया गया है, लेकिन तथ्य और आंकड़े उनके वोट चोरी के आरोप की पोल खोल देते हैं। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें सबसे पहले 15 मार्च, 2024 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, उन्होंने 19 फरवरी, 2025 को भारत के 26वें सीईसी के रूप में कार्यभार संभाला।

खेल
प्रमुख समाचार

डेवोन कॉनवे भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा है। बल्लेबाज डेवोन कॉनवे कन्कशन (सिर की चोट) के कारण भारत के खिलाफ बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज मैट हेनरी को फिट घोषित कर दिया गया है और वे शनिवार को वेलिंगटन में होने वाले दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं।



मैच से एक दिन पहले फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान आपस में टकरा जाने के कारण ये दोनों खिलाड़ी बुधवार को ऑकलैंड में हुए सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। कॉनवे अब इस सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे जबकि हेनरी कन्कशन से उबर चुके हैं और दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं। निक केली, जिन्हें शुरुआत में केवल चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया था, उन्हें कॉनवे की जगह न्यूजीलैंड की टीम में शामिल कर लिया गया है।

इसके चलते केली को न्यूजीलैंड ए टीम से हटा दिया गया है। यह टीम शनिवार को लिंकन में अपनी अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंडिया ए का सामना करेगी। ऑकलैंड के बल्लेबाज डेल फिलिप्स को न्यूजीलैंड ए टीम में केली की जगह शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट की वेबसाइट के एक बयान के अनुसार, मंगलवार को ट्रेनिंग के दौरान फील्डिंग करते समय चोट (कन्कशन) लगने के कारण डेवोन कॉनवे भारत के खिलाफ बाकी बचे वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुने गए बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली, कॉनवे की जगह लेने के लिए आज वेलिंगटन में टीम के साथ जुड़ेंगे। बयान में आगे कहा गया, मैट हेनरी, जो कॉनवे के साथ हुई उस फील्डिंग दुर्घटना में शामिल थे, उन्हें कन्कशन से मुक्त (पूरी तरह ठीक) घोषित कर दिया गया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1718 अंक उछला निफ्टी 25000 के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में धनतेरस के दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स लगातार 7वें सेशन में बढ़त के साथ कारोबार किया। आज कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,718.01 अंक उछलकर 81,028.02 पर बंद हुआ। यानी करीब आठ महीने बाद सेंसेक्स ने फिर से यह अहम स्तर पार किया है। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 493.75 अंक यानी 2.01 फीसदी की बढ़त के साथ 25,030.35 पर बंद हुआ। निफ्टी 27 फरवरी 2026 के बाद पहली बार 25,000 के ऊपर बंद हुआ है। इससे पहले 27 फरवरी को निफ्टी 25,178.65 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में 50 में से 41 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। एमएंडएम, आईसीआईसीआई बैंक समेत एचडीएफसी बैंक शेयरों में 3 से 4 फीसदी तक की मजबूती है।

वाहन खुदरा बिक्री अक्टूबर में 23.8 प्रतिशत घटा : फाडा

नई दिल्ली। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत घटकर 31.72 लाख से अधिक इकाई रह गई। उद्योग निकाय फाडा ने यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के आंकड़ों के अनुसार, बिक्री में यह गिरावट इसलिए भी रही क्योंकि इस साल धनतेरस और दिवाली नवंबर में पड़ रहे हैं, जबकि पिछले साल नवरात्र तथा दिवाली दोनों अक्टूबर में थे। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बाद पिछले साल मांग में आई तेज उछाल का भी असर था। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में 28.35 प्रतिशत घटकर 23.21 लाख इकाई रही, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 4.23 प्रतिशत फिसलकर 5.08 लाख इकाई पर आ गई।

चीनी कारोबारियों ने की 31 रु. से बढ़ाकर 42 रु. करने की मांग

नई दिल्ली। चीनी कारोबारियों के संगठन एआईएसटीए ने सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति किलोग्राम करने की मांग की है। यह मांग ऐसे समय की गई है, जब एक समिति गन्ना किसानों के असंतोष के कारणों की जांच कर रही है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने सरकार द्वारा तय गन्ने के मूल्य को उचित और न्यायसंगत बताते हुए इसका समर्थन भी किया है। संगठन ने 13 अक्टूबर को गठित चार सदस्यीय समिति के समक्ष एक प्रस्तुति में ये मांगें रखीं। नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता वाली यह समिति मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई है। समिति ने चार नवंबर को बेंगलुरु और उसके बाद पुणे में गन्ना किसानों से मुलाकात की। एआईएसटीए का एक प्रतिनिधिमंडल पुणे में हुई बैठक में शामिल हुआ।

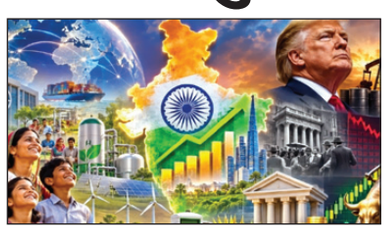
सोने की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में लगातार जारी तेजी के बीच निवेशकों के लिए एक अहम खबर आई है। दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में शामिल Goldman Sachs ने 2026 और 2027 के लिए सोने के अपने कीमत अनुमान में कटौती कर दी है। बैंक का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बने रहने से सोने की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, नए अनुमान के बावजूद बैंक को सोने में आगे बढ़त की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार, 6 नवंबर को स्पॉट गोल्ड करीब 1 फीसदी गिरकर 4,049.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर सोना करीब 5 फीसदी की बढ़त की ओर बढ़ रहा है।

भारत की आर्थिक दिवाली या दुनियाँ में मंदी का महाजाल?

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दीपावली केवल दीपों, खुशियों और समृद्धि का पर्व नहीं है,बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश,निराशा पर आशा और संकट पर संकल्प की विजय का प्रतीक भी है।वर्ष 2026 की दीपावली ऐसे समय में आ रही है,जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ओर गरीबी उन्मूलन,हरित ऊर्जा,घरेलू उपभोग,मुक्त व्यापार समझौतों और आर्थिक सुधारों की नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है,वहीं दूसरी ओर वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव,महंगे कच्चे तेल,चीन के शेयर बाजार की कमजोरी और अमेरिका की अनिश्चित नीतियां विश्व अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर रही हैं। मैं यह मानता हूं कि,इसलिए इस बार भारतीय निवेशकों और आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि आर्थिक उपलब्धियों का उत्सव अवश्य मनाएं, लेकिन वैश्विक जोखिमों को नजरअंदाज करके वित्तीय निर्णय न लें।इस दीपावली हमारा संकल्प होना चाहिए,आर्थिक आत्मनिर्भरता निवेश में विवेक,ऊर्जा में स्वावलंबन, रोजगार में गुणवत्ता और विकास में समानता।क्योंकि असली समृद्धि वह नहीं जो केवल शेयर बाजार में चमके, बल्कि वह है जिसकी रोशनी देश के अंतिम नागरिक के घर तक पहुंचे।29 अक्टूबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वर्ष 2026 भारत के लिए 1991 जैसा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उनका आशय 1991 जैसी भुगतान संतुलन की आपातस्थिति से नहीं, बल्कि बदलती वैश्विकआर्थिक व्यवस्था में भारत को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता से था। उन्होंने आयात प्रतिस्थापन,घरेलू विनिर्माण,निर्यात प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण संसाधनों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।आप सभी को दीपावली की हार्दिक



शुभकामनाएं!

साथियों बात अगर हम गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक उपलब्धि च49.6 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव को समझने की करें तो इस दीपावली भारत के लिए सबसे उत्साहजनक समाचार विश्व बैंक की 30 अक्टूबर 2026 को चर्चा में आई अक्टूबर की इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रिफ रिपोर्ट है। इसके अनुसार वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग प्रतिदिन 4.20 डॉलर की निम्न-मध्यम आय वाले देशों की अंतरराष्ट्रीय गरीबी सीमा से ऊपर आए। इस मानक पर गरीबी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया।वहीं तीन डॉलर प्रतिदिन के अत्यधिक गरीबी मानक पर गरीबी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत हुई। दोनों आंकड़े 2021 की क्रयशक्ति समता यानी पीपीपी पर आधारित हैं। यह उपलब्धि घरेलू उपभोग, रोजगार में वृद्धि,ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती कार्य भागीदारी और खाद्यान्न सब्सिडी जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ी है।वर्ष 2017 से 2023 के बीच रोजगार में लगभग 13.4 करोड़ की वृद्धि भी दर्ज की गई।इसका वैश्विक संदेश स्पष्ट है कि भारत का विशाल घरेलू बाजार निवेश और उत्पादन के लिए आकर्षक बन रहा है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ विश्व बैंक ने आय की असमानता भी रेखांकित की है। शीर्ष 10 प्रतिशत और निचले 10 प्रतिशत के बीच आय का अंतर लगभग 13 गुना है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के बाद अगली चुनौती गुणवत्तापूर्ण रोजगार,बेहतर वेतन,शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थायी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।केवल गरीबी का आंकड़ा घटना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार की वास्तविक क्रयशक्ति बढ़ना भी आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम हरित हाइड्रोजन के 23 अनुबंध- भारत की ऊर्जा कूटनीति को नई ताकत को समझने की करें तो,भारत की दूसरी बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सामने आई है।नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 29 अक्टूबर की जानकारी के अनुसार 2023 में मिशन शुरू होने के बाद भारतीय कंपनियों ने कुल 23 ऑफटेक अनुबंध किए हैं, जिनकी प्रतिबद्धता लगभग 5,55, 610 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन समतुल्य है। इनमें 2026 के दौरान 18 नए समझौते हुए हैं और 70 प्रतिशत से अधिक मात्रा निर्यात के लिए निर्धारित है। इन परियोजनाओं से लगभग 90,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

साय सरकार की दीपावली पर 4670 गरीब परिवारों को पक्के घर की सौगात

बीएलसी में 60,623 और एएचपी में 15,463 आवासों को स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। इस बार की दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। दीपावली पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 4670 नए आवासों की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में यह मंजूरी दीपावली की सौगात बनकर आई है।





इस नई स्वीकृति से पूर्व भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 55 हजार 953 हितग्राहियों तथा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत 15 हजार 463 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके थे। इस प्रकार दोनों घटकों में पहले ही कुल 71 हजार 416 आवासों को मंजूरी मिल चुकी थी। अब 4670 नए आवासों की स्वीकृति के साथ बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60 हजार 623 हो गई है।

एएचपी घटक के 15 हजार 463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के इन दोनों घटकों के अंतर्गत अब तक कुल 76 हजार 086 हितग्राहियों के आवासों को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।

हर पात्र परिवार को पक्का आवास दिलाने के लिये प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवीन आवासों की स्वीकृति पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबके लिए आवास' के संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार किया जा रहा है। उन्होंने सभी नए लाभार्थी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि 4670 नए आवासों की स्वीकृति से हजारों शहरी गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दीपावली पर मिली यह सौगात उन परिवारों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो अपने घर के आंगन में खुशियों के दीप जलाने का सपना संजोए हुए हैं। आवास की स्वीकृति उनके लिए केवल मकान निर्माण का अवसर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ता कदम है।

धनतेरस 2026 : दीपावली में सोना हुआ सस्ता, चांदी में भी नरमी



रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली पर सोने-चांदी के दाम कम हुए हैं। जहां सोना सस्ता हुआ है। वहीं चांदी भी लुढ़की है। राजधानी के सराफा मॉर्केट यानी सदर बाजार और मालवीय रोड में सोना अब डेढ़ लाख से नीचे मिल रहा है। धनतेरस पर शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक है। लोग सोना-चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं।

सदर बाजार, सराफा बाजार, गोल बाजार, मालवीय रोड, पंडरी बाजार, शंकर नगर, लाखे नगर, पुरानी बस्ती, रायपुरा के बाजार में जमकर खरीदारी की जा रही है। वैदिक और पुराणों के मुताबिक, धनतेरस हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाये जाने की परंपरा है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा भी की जाती है। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि धनतेरस के दिन बर्तन की खरीददारी करना शुभ माना जाता है। इसी दिन से दिवाली की तैयारी भी शुरू हो जाती है।

रायपुर के बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकानों को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावट से सजा रखा है। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार में खरीदारी का माहौल बन चुका है। मिठाइयों, बर्तनों, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सजावटी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार त्योहारों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों में सजे रंग-बिरंगे और आकर्षक सामान लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। करवा चौथ के बाद धनतेरस और दीपावली को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह है। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी, जिससे कारोबार को गति मिलेगी। सितंबर के मुकाबले सोना 7,700 रुपए सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,692 प्रति 10 ग्राम बताया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कांकेर के शिल्पकारों से मिट्टी के दीये-कलश खरीदे

कांकेर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपावली के अवसर पर उत्तर बस्तर कांकेर में स्थानीय शिल्पकारों से मिट्टी के दीये और कलश की खरीदी कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस पहल के जरिए उन्होंने स्थानीय कारीगरों के हुनर, मेहनत और परंपरागत शिल्पकला को सम्मान देने की अपील की।



उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाना शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सार्थक कदम है। इससे कारीगरों की मेहनत को उचित सम्मान मिलता है, और उनके परिवारों की आजीविका को भी सहारा मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों से इस दीपावली स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों से मिट्टी के दीये और अन्य उत्पाद खरीदकर उनके जीवन में भी खुशियों की रोशनी लाई जा सकती है। अरुण साव ने कहा कि इस दीपावली बस्तर के स्थानीय शिल्पकारों के बनाए दीये उनके घर में भी रोशनी फैलाएंगे। उन्होंने लोगों से त्योहार की खुशियों में स्थानीय कारीगरों को सहभागी बनाने का आग्रह किया।

बीजापुर से 711 बीजीएल सेल बरामद

बीजापुर। माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने केजी हिल्स के जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में 711 बीजीएल सेल बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इन विस्फोटक सामग्रियों को जंगल में छिपाकर रखा था। इस बड़ी बरामदगी के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को केजी हिल्स के जंगल में माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे जाने की गोपनीय जानकारी मिली थी।

धान खरीदी में बायोमेट्रिक और टोकन की पाबंदियां किसानों को परेशान करने की साजिश : बैज

रायपुर। धान खरीदी प्रक्रिया के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए नए, बायोमेट्रिक सत्यापन और टोकन को लेकर जटिल और दमनकारी नियमों पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को बुरी तरह संकट में डाल दिया है। ओटीपी के स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन की बाध्यता, रकबे के आधार पर टोकन की संख्या सीमित करना, टोकन निरस्त होने का डर, और खरीदी की अवधि में कटौती, यह सब इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह सरकार किसानों को धान बेचने से रोकने और उनका उत्पीड़न करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रच रही है।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि एक तो मौसम की मार, ऊपर से टोकन की कैंची और 15 दिन बाद खरीदी शुरू करके 15 दिन पहले खरीदी बंद करने का फरमान, यह किसानों के साथ सीधी धोखाधड़ी है। भाजपा सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है, जबकि धरातल यह है कि सर्वर डाउन रहने, नेटवर्क की समस्या और बायोमेट्रिक मशीनें फेल होने से किसान घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर होंगे। फिंगरप्रिंट मैच न होने पर किसानों को लौटाया जायेगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए टोकन प्रक्रिया को बेहद सरल, सुगम और विकेंद्रीकृत बनाया था। इसके विपरीत, इस सरकार ने रकबे के आधार पर टोकन की संख्या 2 एकड़ से कम पर सिर्फ 1 टोकन की लिमिट लगाकर किसानों के हाथ-पैर बांध दिए हैं। मौसम की खराबी और खेतों में नमी के बीच 15 दिन पहले खरीदी बंद करने का निर्णय किसानों को औने-पौने दामों पर बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर करने की साजिश है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छोटे और सीमांत किसानों पर एकमुश्त पूरा धान काटने, ढोने और बेचने का भारी आर्थिक और मानसिक दबाव आएगा। पारदर्शिता के नाम पर आप अन्नदाता को अपराधी मानकर फिंगरप्रिंट और टोकन की कैंची से उनका हक क्यों काट रहे हैं? क्या बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह जटिल जाल बुना गया है? 2 एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसानों को सिर्फ 1 ही टोकन देने का क्या औचित्य है? क्या छोटा किसान एक बार में अपना सारा धान काटकर एक ही दिन में केंद्र तक ला सकता है? बायोमेट्रिक सत्यापन फेल होने या सर्वर डाउन होने की स्थिति में यदि किसी किसान का टोकन निरस्त होता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राज्यपाल डेका ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की आत्मीय शुभकामनाएं

रायपुर। प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली के साथ-साथ धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के इस पांच दिवसीय महापर्व पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नए उत्साह के संचार की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल डेका ने कहा कि दीपावली हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और महान परंपराओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पावन त्योहार हमें हमेशा सत्य, सद्भाव और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व हमारे जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का संचार करता है। साथ ही, यह अवसर परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच प्रेम, आपसी विश्वास तथा भाईचारे की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का सशक्त संदेश देता है। राज्यपाल ने अपने संदेश में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों की वास्तविक सार्थकता तभी है जब इनकी खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति और सभी वर्गों तक पहुंचें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पावन अवसर पर समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करें।



सरकार की धोखेबाजी के कारण महिलाओं की दीपावली फीकी : कांग्रेस

रायपुर। सरकार की धोखेबाजी के कारण महिलाओं की दीपावली फीकी हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन सरकार के आने के बाद भाजपा सरकार महिलाओं को भूल गयी। बेरोजगार महिलाएं कैसे दीवाली मनाये? प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार की बदनीयती के कारण प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती थी, बेरोजगार हो गयी है। भाजपा सरकार चुनाव में वादा करने के बाद उनको काम नहीं दे रही है।



प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था पूरे प्रदेश में महिला समूहों को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। सरकार में आने के बाद इसको भूल गए। जब विपक्ष और महिलाओं ने मांग किया तब एक साल पहले घोषणा किया कि पहले 6 जिलों में महिलाओं को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में काम देंगे, फिर सभी जिलों में देंगे। ढाई साल हो गया सिर्फ रायगढ़ जिले के कुछ प्रोजेक्ट में केवल 10 समूहों को एवं दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में काम दिया गया, पूरे जिले में नहीं। सभी

बिजली पोल के लिए खोदे गये गड्ढे से मिला 5 किलो वजनी कुकर आईईडी

नारायणपुर। जिले के थाना कोहकामेटा अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र कुतुल क्षेत्र के ग्राम केहनार के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। जब बिजली पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदने के दौरान जमीन में छिपाकर रखा गया, 05 किलोग्राम वजनी कुकर आईईडी बरामद हुआ। आईईडी की सूचना मिलते ही नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए इसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया है। नारायणपुर एसपी संदीप कुमार पटेल ने कुकर आईईडी मिलने की पुष्टि की है। ग्राम केहनार में बिजली पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदने के दौरान संदिग्ध विस्फोटक मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की 41 वीं वाहिनी के बम निरोधक दस्ते को मौके के लिए रवाना किया गया। संयुक्त टीम ने केहनार-कुतुल मार्ग के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग की। इस दौरान कुतुल कैंप से करीब 07 किलोमीटर दूर फरसबेडा रोड पर 05 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुआ। इसके बाद आईटीबीपी के बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करते हुए नियंत्रित विस्फोट के जरिए आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया।



शक्कर, तेल, प्याज, खाद्य सामग्री की महंगाई से त्योहार कैसे मनाये : कांग्रेस

रायपुर। दीपावली के त्योहार में राशन शक्कर एवं खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने त्योहार का मजा फीका कर दिया। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आम आदमी त्योहार कैसे मनाये? मोदी राज में महंगाई बेतहाशा बढ़ी, गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है तथा त्योहारी सीजन में महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। कुछ दिनों में शक्कर की कीमत में 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्य तेल के दाम दुगुने हो गये है। प्याज 50 रू. किलो पहुंच गया है। आम गृहणी की रसोई की बजट बिगड़ गया है। अच्छे दिनों का वादा कर सरकार में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से परेशान कर रखा है। दाल की कीमते दोगुनी हो गई है, लहसुन 400 किलो, आलू, प्याज, टमाटर एवं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है। दालों की कीमते दुगुनी हो गयी है। दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा, सूजी, दहलन-तिलहन, कपड़े जैसे दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ गये है। दवाओं और अस्पतालों तक में इलाज महंगा हो गया है। एक तरफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घटते इनकम से लोग परेशान हैं, वहीं दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है।



भिलाई के जगदंबा फोम गोदाम में लगी भीषण आग

भिलाई। भिलाई के छावनी चौक स्थित जगदंबा फोम के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे सोफे, गद्दे और फोम समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम के अंदर रखा सामान जलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।



प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में सोफे, गद्दे और फोम से बने अन्य सामान रखे हुए थे। अचानक आग लगने के बाद लपटों ने तेजी से सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गोदाम में रखे फोम और गद्दे जैसे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा सामान जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला और बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, गोदाम में फोम, गद्दे और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी रखा।

रायपुर सहित छह जिलों की बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये 286 करोड़ की नई पारेषण लाइन ऊर्जीकृत

प्रबंध निदेशक शुक्ला द्वारा 400 केवी धरदेही-बिलासपुर पुल पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण

रायपुर। रायपुर सहित छह जिलों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 286 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस धरदेही-बिलासपुर पूल (पावरग्रिड-पीजीसीआईएल) पारेषण लाइन को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। लगभग 50.7 किलोमीटर लंबी इस पारेषण लाइन के चालू होने से रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा तथा भाटापारा-बलौदाबाजार जिलों की विद्युत पारेषण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे अधिक एमवीए विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा और वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग पूरी करने में सहायता मिलेगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) श्री संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक (सबस्टेशन), बिलासपुर श्रीमती कल्पना घाटे तथा कार्यपालक निदेशक, बिलासपुर क्षेत्र, सीएसपीडीसीएल श्री ए.के. अम्बस्थ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



इस 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान चार स्थानों पर अन्य विद्युत लाइनों की क्रॉसिंग का कार्य हॉटलाइन पद्धति से सफलतापूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग का कार्य भी बिना पावर ब्लॉक लिए हॉटलाइन स्ट्रिंगिंग पद्धति से पूरा किया गया। परियोजना निर्माण के दौरान राइट ऑफ वे (मार्गाधिकार) से संबंधित कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आईं। इन चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क से परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर चालू किया गया। नई पारेषण लाइन से अधिक विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

पार्षदों ने ही जोन कार्यालय में लगाया ताला,मूलभूत काम नहीं होने से नाराज

रायपुर। जब नगर निगम के पार्षद अपने ही कार्यालय में तालाबंदी कर दें तब कामकाज का हाल क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी की मुसीबत व परेशानी भी समझ सकते हैं। सफाई,बिजली व पानी की समस्या ही मुख्य कारण हैं और पार्षदों को अब समझ आ गया कि उनके वार्ड में काम हो नहीं रहा। रायपुर नगर निगम के जोन-8 कार्यालय महोबाबाजार में शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। जनता के मूलभूत काम नहीं होने और लगातार अनदेखी से नाराज पार्षद नारेबाजी करते हुए जोन कार्यालय में ताला बंद कर बैठ गए है। मामले पर महापौर,आयुक्त व जोन आयुक्त का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।



बता दें दीपावली से पहले सफाई व रोड लाइट को प्राथमिकता से पूरा करने का आदेश निगम मुख्यालय से जारी हुआ था। आज सड़कों पर कचरों का अंबार हैं और हर वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों का सवाल जब टैक्स लेने के लिए घर दुकान की सीलबंदी तक कर देते हैं फिर सुविधा देने में कोताही क्यों बरतते हैं?

जोन कार्यालय में पार्षदों ने कर्मचारियों को फटकार लगाई और कार्यालय से बाहर जाने को कहा। इसके बाद सभी कर्मचारियों को बाहर निकलवाकर कार्यालय में तालाबंदी कर दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.